जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBIT

My Bush Hunting Days

In the evening, we would find a camping place, sling our hammocks between ever present trees, all conveniently located so that we could tie our hammocks, of course

The Exoticism of the East

The Trailblazing Sculptor Who Defied Boundaries

‘अरे दीवाने ऐसा काम न कर, राम का नाम बदनाम न कर’

शशि थरुर का लोकसभा में यह व्यंगात्मक भाषण इस बात का संकेत है कि राहुल की सोच बदल रही है, बगावती से तेवर दिखाने वाले पार्टी के नेताओं के प्रति

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। शशि थरूर ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी नाम हटाने के निर्णय पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए न्यूक्लियर बिल पर भी अपनी बात रखी।

मनीष तिवारी का एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट) पर भाषण सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद प्रभावपूर्ण हमला था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलतियों को उजागर किया और सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

- पहले राहुल की सोच होती थी, अगर पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं तो पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- पर, अब पार्टी द्वारा शशि थरुर को लोकसभा में खुलकर बोलने का मौका देना, इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का रुख ‘‘बगावती’’ तेवर वाले नेताओं के प्रति कुछ नरम हुआ है।
- दूसरी ओर शशि थरुर भी कुछ सध कर बोल रहे हैं, भाजपा व प्र.मंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते समय।
- शशि थरुर ने यह महसूस किया कि धीरे-धीरे भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र, तिरुअनंतपुरम् में उनके वोट बैंक में सेंध मार रही है और यह थरुर के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी।
- यह ही मनीष तिवाड़ी के बारे में हुआ। मनीष को लग रहा था कि पार्टी में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा, जिसका वे अपने आपको हकदार मानते थे। पर, जब पार्टी ने उन्हें एसआईआर पर राज्यसभा में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहा गया और कांग्रेस के लिए यह सुखद ‘‘डवलपमैंट’’ था।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम में भाजपा के प्रवेश करने से थरुर को झटका लगा है और वे थोड़े शांत पड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरूर की समस्या के पीछे के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

इस परिदृश्य में पार्टी के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर शशि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ बिल पारित

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान करने वाले सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।

राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद आज विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे मंगलवार 16 दिसंबर को ही पारित कर चुकी थी।

इस विधेयक का उद्देश्य बीमा संबंधी तीन कानूनों में संशोधन करना

- राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति प्रदान की, लोकसभा में 16 दिसम्बर को यह बिल पारित हो चुका है।

है। इसमें बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए और भी कई उपाय किये गये हैं।

पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि एक बीमा कंपनी का गैर-बीमा कंपनी के साथ विलय किया जा सकता है या उसे बीमा तथा गैर-बीमा कंपनियों में बांटा जा सकता है। इसके लिए बीमा नियामक से अनुमति लेनी होगी। अब पांच प्रतिशत से कम के हिस्सेदारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत का औद्योगिक उत्पादन घट रहा है’

राहुल गांधी जर्मनी की पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान बी.एम.डब्ल्यु. वर्ल्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्रसिद्ध बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड का गाइडेड टूर करते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि किसी भी देश की सफलता के लिए उत्पादन सबसे अहम है, जबकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

समग्र आर्थिक विकास में मैन्युफैक्चरिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा लहरा रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शोरूम का दौरा करते, वहां मौजूद लग्ज़री कारों को नजदीक से देखते और बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड घूमने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वहां 450 सीसी की एक बाइक भी है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन होता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है, जबकि

- अवलोकन के दौरान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन घटना दुख का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की सफलता की कुँजी उसका औद्योगिक उत्पदान होता है।
- राहुल गांधी की जर्मनी की इस यात्रा की घोषणा लोकसभा के सत्र के दौरान की गई थी तथा इस घोषणा पर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि राहुल गांधी के बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से, राहुल गांधी के अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए।’’

एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ‘‘मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करने की ज़रुरत है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करने की ज़रुरत है।’’

राहुल गांधी दुनिया भर की 117 प्रगतिशील पार्टियों के एक प्रमुख समूह, ‘‘प्रोग्रेसिव अलायंस’’ के निमंत्रण पर जर्मनी के दौरे पर हैं।

अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान, वे बुधवार को होने वाले एक बड़े आईओसी (इण्डियन ओवरसीज़ कांग्रेस) कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे।

यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। इस दौरान एनआरआई से जुड़े मुद्दों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एच वन बी वीज़ा की फीस का सर्वाधिक असर टाटा और इंफोसिस पर पड़ेगा

अब इन कंपनियों को भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए एक लाख डॉलर की वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। अमेरिका के बाहर से नियुक्त किए जाने वाले नए एच-1बी कर्मचारियों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 1,00,000 डॉलर का शुल्क तय किए जाने से आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उद्योग लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है।

यह शुल्क ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाई गई सबसे बड़ी पाबंदी है।

इसका असमान रूप से ज्यादा असर उन बहुराष्ट्रीय स्टाफिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो एच-1बी कर्मचारियों की तलाश कर रहीं कंपनियों के लिए

- ट्रंप के, एच वन बी वीज़ा शुल्क को एक लाख डॉलर करने के फैसले को आउट सोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा हैं। यह उद्योग एच वन बी वर्कस तलाश करने वाली कंपनियों के लिए बिचौलिए का काम करता है। इनमें टाटा कंसलटैंसी, इंफोसिस व कॉग्निज़ैंट शामिल हैं।
- अमेरिका के औद्योगिक विशेषज्ञों का मत है कि भले ही शुल्क वृद्धि को कानून की मदद से रोक दिया जाए, पर, इससे अमेरिकन वीज़ा की मांग में भारी कमी आएगी।

बिचौलिये की भूमिका निभाती हैं। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस कॉर्प शामिल हैं।

मई 2020 से मई 2024 के बीच टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और कॉग्निज़ेंट टैक्नॉलजी सॉल्यूशंस में की गईं लगभग 90 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से मंजूरी मिली थी।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि में इंफोसिस की 93 प्रतिशत से अधिक नई एच-1बी नियुक्तियों, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले भागवत

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के अधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की जानकारी दी गई और बताया गया कि सरसंघ चालक भागवत ने उनसे सांस्कृतिक व शैक्षिक मसलों पर चर्चा की।

राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एनक्लेव में मुलाकात की। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और सरसंघ चालक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) को भारत से अलग करने में मदद देंगे’

बाँग्लादेश के एक नेता के इस बयान पर नाराज़ केन्द्र सरकार ने बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। ढाका में भारतीय उच्चायोग को दी गई धमकियों और बाँग्लादेशी राजनीतिक नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए, भारत ने दिल्ली में मौजूद बाँग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया है।

यह सम्मन बाँग्लादेश की नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के एक नेता द्वारा दी गई उस धमकी के बाद भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ‘‘सेवन सिस्टर्स’’, जो कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, को भारत से अलग करने में मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदुल्लाह को बाँग्लादेश में बिगड़ते

- बाँग्लादेश की नैशनल सिटिज़न पार्टी के एक नेता ने धमकी दी है कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और ‘‘सैवन सिस्टर्स’’ अर्थात् सात पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करेगा।
- भारत में बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बाँग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाँग्लादेश के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणी पर भारत सरकार की नाराज़गी से अवगत कराया गया।

सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उनका बयान, ‘‘विशेष रूप से, उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर खींचा गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आस-पास ‘‘सुरक्षा के लिए खतरा’’ पैदा करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह बाँग्लादेश में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए गए झूठे कथानक को पूरी तरह से नकारता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो मामले की पूरी जांच की है और न इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण साझा किए हैं।’’

बयान में कहा गया, ‘‘भारत के बाँग्लादेश के लोगों के साथ गहरे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में निहित हैं और ये रिश्ते विभिन्न विकासात्मक तथा दोनों देशों की जनता की पहल से मजबूत हुए हैं। हम बाँग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की अपील की है, जो शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत, बाँग्लादेश में मिशनों और पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।’’

‘‘सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करे देंगे’’, छात्रों की पार्टी नैशनल सिटीज़न पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख हसनात अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी ‘‘वर्क फ्रॉम होम’’ करेंगे

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-

- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 18 दिसम्बर से यह आदेश सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर लागू होगा।

होम सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये।

मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित, ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देशों में यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ नैशनल हैरल्ड मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं है भाजपा

भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय ने तकनीकी कारणों के आधार पर ई.डी. को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच की कार्यवाही पर रोक लगाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसंबर। सत्तारूढ़ भाजपा को न्यायपालिका से भी नकारात्मक निर्णय स्वीकार करने की आदत नहीं, इसलिए वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नेशनल हैरल्ड मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने बताया, असल में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) को कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने की संभावना है और उसे नेशनल हैरल्ड की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति को वापस नहीं करना पड़ेगा।

भाजपा के नेताओं ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि हमें इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना होगा और हर कानूनी विकल्प का पता लगाना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, और वह है गांधी परिवार को दबाव में रखना।

दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ‘‘मुंह पर तमाचा’’ करार दिया।

खड़गे ने मीडिया से कहा, ‘‘यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध का

- प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायालय का निर्णय, राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई व गुणवत्ता में कमी के कारण नहीं लिया गया है।
- अतः, यह कहना पूर्ण सच नहीं है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को ‘‘रिलीफ’’ (रियायत) मिली है, न्यायालय से।
- दूसरी ओर, कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से मीडियाकर्मियों के समक्ष कहा कि न्यायालय का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मुँह पर चपत है तथा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

परिणाम था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए तैयार किया गया था। इस निर्णय के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके मुंह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।’’

भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर ‘‘राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने’’ का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ के दावों को खारिज किया।

भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि ‘‘वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं,’’ और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई राजनीति में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है,’’ अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली।

भाजपा नेता के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी।

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट की संज्ञान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओमान के सुल्तान ने हवाई अड्डे पर किया मोदी का स्वागत

मस्कट, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में बुधवार शाम यहां मस्कट पहुंच गए, जहां हवाई अड्डे

- प्र.मंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे।

पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

प्रधानमंत्री ने मस्कट पहुंचते ही ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ बैठक की।

विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

राज के दो साल : भजनलाल सरकार के विश्वास और विकास का लेखा-जोखा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को अपने जन्मदिन के दिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप मे शपथ ली थी। राज्य सरकार दो वर्षों में अर्जित अपनी उपलब्धियों को 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे 15 दिनों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। राज्य सरकार के कार्यों की दो साल की उपलब्धियों की बात करे तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री के पद की यात्रा का सफर सफलतापूर्वक तय किया है। निश्चय ही ग्राम पंचायत के सरपंच से मुख्यमंत्री बनने तक का भजनलाल शर्मा का सफर रोचक और प्रेरणादायी कहा जा सकता है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए यह संकल्प लिया था कि राज्य सरकार प्रदेश की 36 कौमों के विकास के लिए वचनबद्धता के साथ कार्य कर प्रदेश में प्रगति और विकास की नई शुरूआत करेगी। उन्होंने यह संकल्प भी लिया कि विकास सभी के साथ और सबकी भागीदारी से ही होगा। सभी लोग एक साथ चलेंगे तो बदलाव आयेगा और राजस्थान प्रगति के नये सोपान तय करेगा। राजस्थान में भाजपा संगठन से जुड़े एक साधारण कार्यकर्त्ता और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर मोदी और अमित शाह ने समूचे देश को चौंका दिया था। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए अनेक बड़े दावेदारों के नाम सामने आये थे, मगर मोदी ने संगठन से जुड़े एक कार्यकर्त्ता को मुख्यमंत्री का ताज सौंपकर पूरे देश में यह सन्देश दे दिया कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्त्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है।

उपलब्धियों का जश्न

हर सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाती आई है। इसी क्रम में भजन लाल सरकार भी अपनी जन हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अपना विज़न लोगों के सामने रख रही है। सरकार का दावा है कि 2 साल में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जन हितैषी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। इस अवधि में भजनलाल सरकार के किसी भी मंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं लगा, हालांकि अधिकारियों की कार्यशैली पर अवश्य सवालिया निशान लगे। दो वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है। भजनलाल सरकार का दावा है कि 2 साल में ही जनता की सरकार के रूप में संवेदनशीलता से किये कार्य का परिणाम है कि आज समाज के सभी वर्ग सरकार के कार्यों से बेहद संतुष्ट है। सरकार का दावा है कि इस अवधि में सरकार लगातार जनता के बीच गई और जनकल्याणकारी कार्यों को अमलीजामा पहनाया। राज्य मंत्रीपरिषद के सदस्य प्रदेशभर में भ्रमण कर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे है।

आंकड़े सच बोलते है

यह दावा भी किया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच सालों की अपेक्षा भजनलाल सरकार के दो सालों में अधिक बेहतर कार्य किये है। इसे 5 साल बनाम 2 साल के आंकड़े सच बोलते है के शीर्षक के माध्यम से प्रदर्शित किये जा रहे है। इन आंकड़ों में विशेष रूप से नहरी तंत्र से सृजित सिचाई सुविधा, फार्म पोंड, ओडीएफ प्लस गांव, निर्मित सड़कों की लम्बाई, सड़कों से जोड़े गए गांव, बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि, स्कूली छात्रों को टैबलेट/ लेपटॉप वितरण छात्राओं को स्कूटी वितरण, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, महाविद्यालयों के भवन निर्माण, नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन, सेटेलाइट अस्पताल स्थापना,कौशल प्रशिक्षण और गौशालाओं को सहायता की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर दावा किया गया है कि हमारी सरकार ने दो सालों में ही पांच सालों को पछाड़ दिया। उपलब्धियों के इन आंकड़ों को देश भर में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है।

> **मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यो के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा।**

मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में जनसेवा की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे को जन आंकाक्षाओं के अनुरूप मजबूत बनाने में जुटे हैं। भजनलाल सरकार महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और दिव्यांग जनों सहित हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। जनता से सीधे जुड़े विभागों ऊर्जा उत्पादन, सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल, जल संसाधन, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य किये। सरकार का दावा है कि हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है। चुनाव के समय जनता से किए गए 392 संकल्पों में से 274 या तो पूरे किए जा चुके हैं या प्रगति पर हैं। प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरुरत है तभी मुस्कराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा। आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं। सरकार के दावे के विपरीत विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया जिससे हर वर्ग दुखी और परेशान है। कानून व्यवथा छिन्न-भिन्न है। रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। आमजन बेहाल है ऐसे में खुशहाली की बात करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार घोषित किया मगर इसी पर्ची सरकार ने दो साल में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की पहल की अपितु आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए हैं।

साफ़ सुथरी छवि और ईमानदार नेता

मुख्यमंत्री भजनलाल की छवि एक साफ़-सुथरे, मेहनती, समर्पित और ईमानदार नेता की है। जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ प्रदेश के विकास में जुटे है। आम आदमी की सोच है प्रदेश के बहुमुखी विकास में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और कुशासन प्रगति और विकास के दुश्मन के रूप में उभरे है। जब तक इन पर काबू नहीं पाया जायेगा तब तक विकास और प्रगति एकांगी होगी। हर सरकार लोक कल्याण का वादा करती है मगर लोक कल्याण के मार्ग में अवरोध बने इन कारकों को समाप्त करने की दिशा में कोई ठौस कारवाही नहीं करती। चूँकि राजनेताओं के हित इनसे जुड़े है इसलिए इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक समाज से यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, हम भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगते रहेंगे। भ्रष्टाचार आज भी समाज को खोखला कर रहा है। इस बेतरणी में सभी अपने हाथ धोना चाहते है। ऐसा लगता है राजस्थान में भ्रष्ट कर्मियों से अपना नापाक गठजोड़ स्थापित कर लिया है।जन प्रतिनिधियों और सरकारी कारिंदों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग के प्रकरणों का खुलासा आये दिन मीडिया में सुर्खियों में पढ़ने को मिल जाता है। जनता के खून पसीने की कमाई को हड़प करने का जरिया भ्रष्टाचारियों ने अपना लिया है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार ने अपना दामन चहुंओर फैला रखा है। राजस्व, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेडीए, स्थानीय निकाय, सिंचाई, जलदाय, रसद, सड़क, पंजीयन जैसे दर्जनों कार्यालय हैं जहां बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता। जब तक मुट्ठी गर्म न की जाए तब तक कोई काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार एक संचारी बीमारी की भांति इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों को अपना भविष्य अंधकार से भरा नजर आने लगा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना चाहते है। ऐसे में प्रदेशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर जनता को राहत प्रदान करे।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

सेवा शिविर: सुशासन की अवधारणा को नई दिशा

जोगाराम पटेल

राज्य के शासन-प्रशासन का वास्तविक मूल्यांकन उसकी नितियों और निर्णय से आम नागरिक के जीवन में मिलने वाली प्रत्यक्ष राहत और सुविधाओं से किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा शिविर इस कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। यहां सरकार दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है।

सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन और सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्षों से यह शिकायत रही कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं फाइलों, प्रक्रियाओं और दफ्तरों के बीच उलझकर रह जाती हैं। सेवा शिविरों ने इस मानसिकता को तोड़ा है। यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां प्रशासन, योजनाएं और समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यह बदलाव अपने आप में सुशासन की परिभाषा को नया आयाम देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन शिविरों की शुरुआत की गई। इससे यह अभियान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की व्यापक राष्ट्रीय सोच से जुड़ गया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक निरंतरता का संकेत है, जहां केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर शासन का लक्ष्य अंत्योदय है।

सेवा शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां 18 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जिस कार्य के लिए आम नागरिक को कई विभागों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वही काम अब शिविर स्थल पर कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, भू-राजस्व शुद्धिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतें आदि सभी सेवाएं अब कतार, फाइल और देरी से मुक्त होकर त्वरित समाधान का रूप ले चुकी हैं।

अब तक 2 लाख से अधिक जाति प्रमाण पत्र, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र, 1.53 लाख भू-राजस्व शुद्धिकरण प्रकरण और 1.24 लाख नामांतरण मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये आंकड़े आम नागरिक के समय, श्रम और सम्मान की बचत का प्रमाण हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर: पंचायत स्तर पर सुशासन

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गांव छूटे नहीं। राजस्व विभाग मौके पर ही नामांतरण, नोटिस तामील और प्रमाण पत्र वितरण कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल सर्वे कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत, मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच और एनीमिया परीक्षण जैसी योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा अब तक 2.60 लाख से अधिक मवेशी बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालकों के लिए बड़ी सुरक्षा है। कृषि विभाग बीज किट वितरण के माध्यम से किसानों को राहत दे रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग मौके पर ही राहत राशि स्वीकृत कर रहा है। यह सब मिलकर ग्रामीण सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत करता है।

शहरी सेवा शिविर: सुविधा के साथ सौंदर्य

शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर केवल प्रमाण पत्र और आवेदन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी ढांचे में प्रत्यक्ष सुधार का माध्यम भी बन रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स की स्थापना जैसे कार्य शिविरों के साथ-साथ किए जा रहे हैं।

नगर निकायों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन आदि कार्य भी इन्हीं शिविरों में किए रहे हैं। अब तक 1.95 लाख से अधिक पट्टों का वितरण, 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरणों का निस्तारण और 1.48 लाख जनधन खातों का संचालन किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि शहरी सेवा शिविर प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ जीवन गुणवत्ता सुधार का भी माध्यम बन चुके हैं।

सेवा शिविरों का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। शिविरों के माध्यम से 24.36 लाख मरीजों का उपचार, 10.77 लाख लोगों की टीबी व एनसीडी स्क्रीनिंग और 17 लाख किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की जा चुकी है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर 95,800 से अधिक आवेदन स्वीकृत, जन आधार योजना में 1.13 लाख लाभार्थी, 25 हजार स्वनिधि ऋण और 75,600 वय वंदन कार्ड जारी होना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सुरक्षा अब कागजों तक सीमित नहीं रही। इन शिविरों का सबसे बड़ा प्रभाव जन विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में सामने आया है। वर्षों से लंबित नामांतरण, प्रमाण पत्र या बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं अब कुछ घंटों में सुलझ रही हैं। इससे न केवल जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक इकाइयों की कार्यकुशलता और जवाबदेही भी मजबूत हुई है।

नगरीय निकायों में दी गई विशेष रियायतें जैसे बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी से हजारों परिवारों और व्यापारियों के लिए सीधी राहत हैं। यह दिखाता है कि सरकार नियमों के साथ-साथ संवेदनशीलता को भी उतना ही महत्व दे रही है।

सेवा शिविर आज पारदर्शिता, सरलता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता का संयुक्त उदाहरण बन चुके हैं। घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की सतत निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह पहल केवल आयोजन न बनकर रह जाए, बल्कि स्थायी प्रशासनिक सुधार का माध्यम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह सोच कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी शासन का केंद्र हो, सेवा शिविरों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है। यह पहल बताती है कि जब राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छाशक्ति एक दिशा में काम करें, तो सुशासन केवल नारा नहीं, बल्कि जन-जीवन का अनुभव बन जाता है। सेवा शिविर वास्तव में यह संदेश दे रहे हैं कि सरकार अब दरवाजे पर दस्तक देने वाली संस्था बन चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है।

–जोगाराम पटेल,
संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री

महाभियोग को बनाया दबाव बनाने और प्रतिशोध का एक साधन

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

आज भारत राजनीति में गिरावट, राजनीतिक पार्टियों में संवैधानिक नैतिकता के पतन और भारत के लोगों के प्रतिनिधियों के पतन का गवाह बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बिना 100 सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना, भारत के संविधान में अविश्वास, न्यायपालिका में भरोसे की कमी और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका को धमकाने और प्रतिशोध लेने का एक हथियार बनाया है।

यह मामला अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है। मूल रूप से यह मुद्दा संपत्ति जो कि थिरुप्परंकुंद्रण पहाड़ी पर स्थित है पर नागरिक अधिकारों से संबंधित है, जिस पर 1923 में ही प्रिवी काउंसिल द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा का मुकदमा निर्णितहोगयाथा । मद्रास उच्च न्यायालय ने1996 के आदेश में मुस्लिम समुदाय की सीमांकित भूमि से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। 2005 में शांति समिति के प्रस्ताव में भी इसे मान्यता दी गई थी। चूंकि यह मुद्दा अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है, इसलिए जो एक पक्ष के लिए पवित्र और पावन है, वह दूसरे पक्ष के लिए समान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दरगाह में पशु बलि के प्रयास पर रोक लगा दी गई थी।

याचिका में बताई गई घटनाओं का क्रम, भारत में आपसी भाईचारे के लिए कुछ बातें एकदम साफ़ कर देता है कि दोनों समुदायों को शांति से साथ चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकारों की कुर्बानी की कीमत पर नहीं। संवैधानिक नैतिकता के दायरे में सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर रीति-रिवाजों और परंपराओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल है, वह है भक्तों की भूमिका और कर्तव्य, जहाँ धार्मिक संस्था के ट्रस्टी वैध पारंपरिक प्रथाओं को निभाने और संरक्षित करने में विफल रहते हैं। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मंदिर के प्रबंधन को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि वे दीपाथून नामक पत्थर के मंदिर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाएँ जोकि दरगाह से 50 मीटर दूर स्थित है और न्यायिक आदेश की अनुमति से तीन गुना दूर है। याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रबंधन के कार्तिगई दीपम को अलग जगह पर जलाने के निर्देशों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को लोकस स्टैंडी, रेस ज्युडिकाटा, पूजा स्थल अधिनियम जैसी आपत्तियों पर सम्पूर्ण विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन/देवस्थानम को निर्देश दिया कि वे सामान्य स्थानों के अलावा दीपाथून पर भी कार्तिगई दीपम जलाएँ और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन केवल अवमानना याचिका दायर करने और कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों की टीम को याचिकाकर्ता और उसके दस साथियों को सुरक्षा प्रदान करने और कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश देने के बाद ही किया गया।यह बताना ज़रूरी है कि दरगाह कमेटी ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है जिसे लागू किया जाना है। राज्य सरकार ने विवादित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। भक्त याचिकाकर्ता ने खुद दीपक जलाने का दावा नहीं किया था, बल्कि वह चाहता था कि मंदिर ट्रस्ट उन परंपराओं को बनाए रखे जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हैं। जब मंदिर ट्रस्ट ने आदेशों का पालन नहीं किया, तब सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए केवल दस लोगों को दीपक जलाने की अनुमति दी गई, जो दरगाह से तयशुदा दूरी से तीन गुणा दूरी पर है। घटनाओं को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं, यह भारत के संविधान की योजना, आलोच्य आदेश के खिलाफ लंबित अपील, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य अन्तोगत्वा, केंद्र सरकार की सीआईएसएफ एजेंसी ने आदेश का पालन करवाया, जिससे कानून के शासन को बनाए रखा गया।

तमिलनाडु राज्य का यह अवज्ञापूर्ण कार्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए ली गई शपथ के अक्षर और भावना का उल्लंघन है। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि राज्य का नौकरशाही तंत्र न्यायपालिका के कानूनी आदेशों और उच्च अधिकारी के अवैध आदेशों और उनके परिणामों के बीच अंतर को समझने में विफल रहा। यह संविधान के प्रति अनादर और राजनीतिक दलों की हताशा को दर्शाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेंलंबित आदेश पर अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना महाभियोग प्रस्ताव का विकल्प चुना। निष्कर्ष के तौर पर, यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है जहाँ एक राजनीतिक विचारधारा संवैधानिक अदालत द्वारा न्यायिक फैसले पर असंतोष व्यक्त करती है, उस जज पर दुराचार और अक्षमता का आरोप लगाया जो भारत के संविधान के दायरे में फैसला सुनाता है। यह कहना कि यह विवाद धार्मिक प्रकृति का है, गुमराह करने वाला है। इसका इस्तेमाल मीडिया में अफवाहें फैलाने और वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र का उल्लंघन है।

सूर्यप्रतापसिंह राजावत
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

जाटोली गांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण से जलभराव, ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया, घरों में घुसता है बारिश का पानी

- **आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन व गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है**
- **ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की**

अलवर, (निसं)। जाटोली में नवनिर्मित सीसी सड़क में अनियमितताओं के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है।

गांव निवासी राकेश कुमार गौतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क की अधिक ऊंचाई के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे घरों में पानी भर रहा है और ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें निर्धारित मानकों और शर्तों की अनदेखी की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी सड़क निर्माण परियोजनाओं में जल निकासी, ऊंचाई और गुणवत्ता संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं। हालांकि, ठेकेदार ने कथित तौर पर निजी लाभ के लिए इन शर्तों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जाटोली गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण को दोबारा सही मानकों के अनुसार कराने की भी अपील की है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 18 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:07 तक, धृति योग दिन 3:06 तक, विष्टि करण दिन 3:46 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:07 तक है। भद्रा दिन 3:46 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि, श्री जय प्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:31 तक, चर 11:06 से 12:23 तक, लाभ-अमृत 12:23 से 2:58 तक, शुभ 4:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:32 तक

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण बढ़ेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

आरजीएचएस योजना में वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत

चिकित्सा विभाग ने बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से किया डी-पैनल

- राज्य सरकार ने 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को किया निलंबित
- अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए कंट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ एवं एंटी फ्रॉड यूनिट
- अस्पतालों को 1260 करोड़ और फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से सभी सेवारत व सेवानिवृत कर्मचारी एवं अधिकारी, मंत्रीगण, विधायक, पूर्व विधायक को व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज उपलब्ध करवाकर आईपीडी, डेकेयर, ओपीडी, जांच एवं दवाइयों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना से लाभार्थियों को प्रदेश में व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज सुविधा मिल रही है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में 687.38 करोड़ रुपये, 2022-23 में 3057.38, 2023-24 में 3519.40 और वित्त वर्ष 2024-25 में 4290 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इस योजना में प्रतिदिन औसत 45 हजार से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत बेहतर समन्वय व मॉनिटरिंग की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। इससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।

आरजीएचएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आईपीडी में 1311.25 करोड़ रुपये, डे-केयर में 411.78 करोड़ रुपये, ओपीडी परामर्श व जांच पर 649.99 करोड़ रुपये एवं दवाईयों पर 1889.85 करोड़ रुपये के दावे तथा वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपये एवं फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरजीएचएस में अनियमितता करने पर मंगलवार को बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से डी-पैनल कर 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितता व धोखाधड़ी करने पर विभाग ने वर्ष 2025 में 10 मामलों में संबंधित फार्मेसी, चिकित्सक व लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

आरजीएचएस सुविधा को बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 159 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को योजना से निलंबित कर टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है तथा 5 अस्पतालों को योजना से डी-पैनल किया गया है। आवश्यक सुनवाई कर अस्पतालों के विरूद्ध 26.12 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई, जिसमें से 25.07 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 65 निजी चिकित्सालय योजना से निलंबित हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में अप्रैल 2025 से अब तक 137 फार्मेसी को निलंबित कर उनकी टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है। इसके अतिरिक्त योजना अन्तर्गत कैशलेस दवा वितरण से इन्कार करने के कारण 411 फार्मेसी स्टोर एवं ड्रग लाइसेंस लैप्स हो जाने के कारण 944 फार्मेसी स्टोर को निलंबित किया गया है। साथ ही, मेडीकल स्टोर्स के विरुद्ध 39.79 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई गई है, जिसमें से 35.42 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसी प्रकार अप्रैल 2025 से अब तक कुल 4 लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितताओं में संलिप्त आरजीएचएस कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1032 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक किये गये हैं। गंभीर अनियमितता व धोखाधड़ी के 61 मामलों में कार्मिक को सेवा से निलंबित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। इनमें से 23 कार्मिकों एवं 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार 11 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 493 लाभार्थियों के विरूद्ध कार्ड के दुरूपयोग के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भेजे गये हैं। इनमें से पुलिस विभाग के 137, स्कूल शिक्षा विभाग के 258, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 60, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 23 एवं आयुर्वेद विभाग के 15 कार्मिक सम्मिलित हैं। दावों के भुगतान के लिए एफआईएफओ प्रक्रिया आरजीएचएस योजना में विभिन्न अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, फार्मेसी, जांच केन्द्र व कार्डधारकों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल एवं परफॉरमेंस ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। योजना में क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए निरंतर जांच व सुनवाई की जा रही है।

जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किए पांच आरोपी

- आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल व उनके बेटे हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल (उर्फ गोलू), श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर एवं लायजनिंग अधिकारी उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं। जिन्हें जयपुर शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया था। इसमें श्याम ट्यूबवेल कंपनी, उसके मालिक पदमचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी और उसके मालिक महेश कुमार मित्तल पर पीएचईडी के बहरोड़ अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी, नीमराना सहायक अभियंता राकेश चौहान तथा कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार से सांठगांठ कर जल जीवन मिशन के टैंडर हासिल करने के आरोप लगे थे।

इन आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का उपयोग करने और मनमाने ढंग से मेजरमेंट बुक (एमबी) भरकर करोड़ों रुपये की अवैध प्राप्ति करने का भी आरोप है। एसीबी के पास आरोपियों की आपसी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जो मिलीभगत के सबूत है।

इस मामले की त्वरित जांच के लिए एसपी महावीर सिंह राणावत की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। जिसमें एएसपी हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र और महावीर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। एसआईटी ने तकनीकी सबूतों और ट्रांसक्रिप्ट का गहन विश्लेषण किया। पहले छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। शेष फरार आरोपियों में से इन पांच को जयपुर के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि 2023 में आरोपियों को पीएचईडी अधिकारियों से 2.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते-देते पकड़ा था। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह और एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में एएसपी भूपेंद्र की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में पूछताछ और आगे की जांच जारी है।

टीकाराम जूली ने न बजट पढ़ा और ना ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझी : चतुर्वेदी

- राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

जयपुर। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट ठीक से पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है। कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है और तथ्यों से दूर बयानबाजी कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब राजस्थान की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासनकाल में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के संसाधनों में लगातार वृद्धि हो रही हैं।

ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक इन मुद्दों पर केवल राजनीति करती रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर ईआरसीपी पर काम शुरू किया है। इसी तरह यमुना जल को लेकर 50 वर्षों तक केवल राजनीति हुई, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद इस दिशा में ठोस पहल हुई है और डीपीआर तैयार की जा रही है।

अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में लगातार ठोस और परिणामोन्मुख कार्य कर रही है। पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन कर सरकार ने विकास और निवेश को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ईमानदार है तो विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए। इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल और वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यों की तुलना हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों में कई सुधार किए हैं। उनके लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मौजूदा सरकार मनरेगा में समय पर भुगतान, स्थायी विकास से जुड़े कार्यों और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार देने पर फोकस कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अफवाह, भ्रम और नकारात्मकता के सहारे राजनीति कर रही है।

सांस्कृतिक संध्या में लोक-संगीत और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति नजर आई

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया।

- भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुन और कठपुतली शो रहे आकर्षण का केंद्र
- बॉलीवुड एक्टर, राइटर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा

जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार के कार्यकाल के शानदार दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केन्द्र में 15 दिसम्बर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में तीसरे दिन बुधवार को सांस्कृतिक संध्या में भपंग वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुनों और काठ की पुतलियों की जीवंत अदाओं ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

पर्यटन विभाग के सहयोग से सुसज्जित सांस्कृतिक संध्या में यूसुफ खाँ एवं उनके समूह ने भपंग वादन के माध्यम से कैसो आ गयो जमानो रे और दुनिया में भाया देख ले जैसे लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियाँ बटोरीं। वहीं चूरू के श्याम मित्र मण्डल ने चंग की जोशीली थाप और बांसुरी की मधुर तान के साथ लोकधुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कठपुतली लोक कलाकार राजू भाट रहे, जिन्होंने ढोलक की थाप पर उंगलियों पर काठ की पुतलियों को नचाते हुए महाराजा अमरसिंह की कहानी प्रस्तुत कर दर्शकों को जीवंत अनुभूति कराई। प्रदर्शनी देखने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर, राइटर और डायरेक्टर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि लोक कलाओं को संजोकर रखा जाए, यह कलाएं हमारी धरोहर हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह निःशुल्क कला प्रदर्शन है किन्तु कठपुतली कला अद्भुत और अलौकिक है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया, उनका स्वागत किया, वहीं कलाकारों को भी मंच पर सम्मानित किया। इससे पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी क्षिप्रा शर्मा किस्सागोई कला के अंतर्गत मोर और मोरनी की लोककथा सुनाकर श्रोताओं को कथाओं की दुनिया में ले गईं। इस अवसर पर विभाग की सहायक निदेशक कविता जोशी ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पिछले साल की तुलना में 14200 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिला

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस से बदली तस्वीर, प्रदेश के राजस्व में हुई वृद्धि

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व सुधार और वृद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटलाइजेशन और तकनीक के प्रयोग से जीएसटी, स्टैम्प, पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर टैक्स और नॉन टैक्स श्रेणियों में संरचनात्मक सुधारों को अमल में लाया गया, डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई तथा डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई गई। इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने टैक्स एवं नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार करते हुए डिजिटल निगरानी और डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग किया है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग, अवैध खनन तथा अन्य राजस्व लीकेज गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से राजस्थान के राजस्व संग्रह में निरंतर और मजबूत वृद्धि संभव हुई है। प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 14 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

विभाग द्वारा रेवेन्यू इंटेलीजेंस आधारित विश्लेषण को सुदृढ़ कर 45 से अधिक डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स तैयार की गई, जिनसे फर्जी बिलिंग की पहचान संभव हुई और इस पर प्रभावी रोक लगी। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल मिलान, रिटर्न प्रोफाइलिंग तथा आधुनिक आईटी टूल्स के माध्यम से हाई रिस्क करदाताओं की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पिछले दो वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए हैं। इन कार्रवाईयों के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती और अवैध भट्टियां को नष्ट कर तस्कर गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे राजस्व लीकेज को प्रभावी रूप से रोका गया।

राज्य सरकार द्वारा तकनीकी सुधारों को अपनाते हुए ई-एक्साइज प्रणाली, क्यूआर आधारित ट्रैकिंग, डिजिटल परमिट सिस्टम और एंड-टू-एंड सप्लाई चेन मॉनिटरिंग को लागू किया।शराब दुकानों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करते हुए ई-लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी है।

राज्य में स्टांप एवं पंजीकरण में डिजिटल सुधारों के प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ई-पंजीयन, ई-ग्रास, राज स्टाम्प और 181 हेल्पडेस्क जैसी ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इससे नागरिकों के समय और लागत दोनों की बचत हुई है। गत दो वर्षों में विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया है, जिससे 20 हजार 599 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे फ्लैटों की खरीद, टीडीआर और डेबट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की गई है।

जयपुर के नगेंद्र शर्मा सीआईएसफ में डीआईजी बने

जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर जयपुर निवासी नगेंद्र शर्मा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में वरिष्ठ कमांडेंट से पदोन्नत कर उपमहानिरीक्षक बनाया गया है। यूपीएससी 2004 बैच में चयनित नगेंद्र शर्मा ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई राज्यों और संवेदनशील स्थानो पर अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में नगेंद्र शर्मा प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं एनडीआरएफ में दे रहे हैं और भुवनेश्वर में पदस्थापित हैं और आपदा के प्रति संवेदनशील उडीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य से संबंधित आपदा प्रबंधन का दायित्व देख रहे है। वर्ष 2024 में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के मद्देनजर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक भी प्रदान किया गया है।

कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है : मुख्यमंत्री

- जालौर की जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने ली कांग्रेस पर चुटकी ली
- हम विद्यालयों में लगवा रहे हैं कैम्प, कांग्रेसी इनमें जाएं और आंखों की जांच कराएं : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2 साल में हमने इतने काम कर दिए जितने कांग्रेस ने पांच साल में भी नहीं किए। जब मैं कांग्रेस के लोगों को इन कामों को बताता हूं तो इनको दिखता नहीं है और कहते हैं कि विकास कहां है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का कांग्रेस का काम है। अगर आपके पास आंकडे हैं तो बताइए आपने कितना काम किया और हमने कितना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर विद्यालय में आंखों के कैम्प लगवा रही है जिसमें आंखों की जांच भी होगी और चश्मा भी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि वो भी इन शिविरों में जाएं और आंखों की जांच कराएं, आवश्यकता होने पर चश्मा भी लें जिससे उनको दो साल का विकास दिख जाएगा।

नेशनल हैराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, धक्का-मुक्की में कई घायल

- आधे घंटे के हंगामे के बाद डोटासरा व जूली के साथ कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

जयपुर (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च का आव्हान किया गया था, परंतु पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होती रही। जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कर रहे थे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे। जहां बैरिकेड्स पार करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मनीष यादव का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए।

प्रतर्वन निदेशालय के कथित दुरूपयोग के आरोप के साथ भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जयपुर में शहीद स्मारक पर रोका।

करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, मनीष यादव, विद्याधर चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को बसों में भरकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। जहां कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ की गई। लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। जिससे सच्चाई सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी। उन्होंने इसे सत्य की जीत और सरकार के लिए करारा जवाब बताया।

मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आज करेंगे शुभारंभ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित होटल मैरियट में इस कॉनक्लेव का शुभारंभ करेंगे। शर्मा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव में राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन व 'मेरी लाइफ-सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट' पोस्टर का विमोचन करेंगे। इस दौरान संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गत दो वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ डूइंग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किए है। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सम्मति संचालन तंत्र में ऑटो-रिन्यूअल सुविधा की शुरूआत की गई है।

कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही : जोगाराम पटेल

- कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ, जनता राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी : बालमुकुंदाचार्य

जयपुर (कासं)। संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेसी नेताओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था।

पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस, भाजपा सरकार की 'राइजिंग राजस्थान' पहल पर भी अनावश्यक सवाल उठा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में साहस है तो वह 'राइजिंग राजस्थान' के तहत हुए कार्यों और निवेश प्रस्तावों का खंडन करके दिखाए।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी कमियां हैं। न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं। कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि अनुसार पूरा किया जाए। इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामला समाप्त हुआ है।

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता अब कांग्रेस की नकारात्मक, भ्रम फैलाने वाली और राष्ट्रिवरोधी राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है। कांग्रेस को यह भय सताने लगा है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। इसी डर के कारण कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है, कभी वोटर लिस्ट को दोष देती है और अब तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग से चार लोग जिंदा जले, तीन की मौत

तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले, एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया

अलवर, (निसं)। अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात एक पिकअप में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की बुरी तरह जलने से मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर झुलसे व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसा जिले के रैणी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब एक बजे हुआ। एएसआई मोहम्मद आमीन ने बताया कि अंदाजा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है। टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई। तीनों शव सीट पर चिपके हुए मिले। एएसआई ने बताया पिकअप में मिले तीन लोगों के शवों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आग लगने पिकअप गाड़ी पूरी तरह से जल गई।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में आग देखने के बाद कई गाड़ियां मौके पर ही रुक गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी।

पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

- बताया जा रहा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है, टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई
- पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, इसके बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी

इसके बाद ही साफ होगा कि गाड़ी को किसने टक्कर मारी थी। शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार : टोंक जिले की स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अवैध हथियारों के विरुद्ध के तहत उनकी टीम ने निवाई सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को क्षैत्र स्थित मुंडिया कट के पास से आरोपी मोहिद खान पुत्र रुस्तम खान निवासी खिड़की थाना बरौनी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई।

डीएसटी टीम ने आरोपी को निवाई सदर थाना पुलिस को सौंप दिया, जिसके खिलाफ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवाई सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

दस्तावेज सत्यापन की तिथि बढ़ाई

अजमेर, (कासं)। पटवार परीक्षा 2025 के तहत सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि आगामी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। उप निबन्धक (भू अभिलेख) रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकाधिक अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में तीन दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए 17 दिसम्बर तक दस्तावेज सत्यापन कार्य हुआ जिसमें साढ़े छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सत्यापन का लाभ मिला। शेष अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी 22 दिसम्बर की शाम पांच बजे तक दस्तावेज सत्यापन कराने को कहा गया है। यह कार्य यथावत आरआरटीआई जयपुर रोड अजमेर में सम्पादित होगा।

परीणाम जारी

अजमेर, (कासं)। 11वीं बटालियन आरएसी वजीराबाद रियर मुख्यालय नारेली के लिए कॉस्टेबल सामान्य की भर्ती शारीरिक दक्षता एवं माप तौल परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इसे राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। 11वीं बटालियन के कमाण्डेन्ट केवल राम ने बताया कि बटालियन के रियर मुख्यालय नारेली के नोटिस बोर्ड पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

जोधपुर की कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के कायलाना झील में बुधवार सुबह युवक-युवती के शव मिले। झील किनारे एक एक्टिवा, बैग, मोबाइल और जैकेट भी मिला। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है। युवक-युवती दोनों पड़ोसी थे। हादसा राजीव गांधी नगर थाने का है।

एएसआई रावल राम ने बताया कि हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और चेष्टा धोला (20) पुत्री विकास धोला मंगलवार को खांडा फलसा थाना क्षेत्र स्थित अपने घरों से निकले थे। दोनों एक ही जाति के थे और पड़ोसी थे। परिवार ने मंगलवार को सिटी पुलिस थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गोताखोरों की टीम ने दोनों को बॉडी को बाहर निकाला।

- मामला आत्महत्या या किसी अन्य कारण से डूबने का है, इसकी जांच की जा रही है

एएसआई ने बताया कि मंगलवार शाम को करीब पांच बजे कायलाना झील के आगे तखत सागर के पास दोनों की स्कूटी और बैग मिले थे। इसके बाद कायलाना पुलिस चौकी के सिपाही दिनेश सोडा और गोताखोर भरत चौधरी के साथ मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने के कारण दोनों के शव नहीं मिल सके। इसके बाद आज सुबह फिर से अभियान शुरू किया। शव गहरे पानी में फंसे हुए मिले। इस दौरान मौके पर परिजन भी मौजूद थे। शवों को एमडीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला-पाली) राज.
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी (आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com
क्रमांक : न.पा.सा./2025/4232-4234 दिनांक 15.12.2025
-:: Notice Inviting Bid ::-
Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.
UBN NO :- DLB2526WSOB27334
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी
राज.संवाद/सी/25/15940

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
क्रमांक :-न.प.सु/विकास शाखा/2025/9280 दिनांक :- 11.12.2025
:-ई-निविदा सूचना-2025-26:-
नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 22.12.2025 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2526WSOB26910), (DLB2526WSOB26911), (DLB2526WSOB26913), (DLB2526WSOB26914) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।
आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ
राज.संवाद/सी/25/15979

चोरी करने वाले तीन बदमाश सात घंटे में गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर के अखेपुरा थाना पुलिस ने दुकान में चोरी कर नकदी पार करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई घनश्याम शर्मा ने बताया कि परिवादी महेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अशोका टॉकीज से पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित उनकी नवकार ट्रेडर्स के नाम से दुकान व गोदाम में चोरों ने वारदात की थी।

- छत का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और गल्ला तोड़कर 65 हजार रुपये ले गए थे

परिवादी के अनुसार सोमवार रात चोर दुकान के पीछे छत पर चढ़े और सीढ़ियों का ताला तोड़कर नीचे उतरे। इसके बाद दराज से 65 हजार रुपये नकद और एक आधार कार्ड चोरी कर ले गए। परिवादी ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे थाने में शिकायत दी।

पुलिस ने दुकान में चोरी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना के आधार पर कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल गिर्राज की टीम ने तीन आरोपियों-लोकेश कुमार निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, राहुल बैरवा निवासी गाय वाला मोहल्ला और राहुल कोली निवासी ज्योति नगर, 200 फुट रोड को मंगलवार शाम छह बजे ही डिटेन कर थाने ले आए। बुधवार को सात घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया है। वारदात में चोरी गई नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

सड़क नहीं बनने पर कलैक्टर व एसडीएम की संपत्ति कुर्क होगी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तार भी किया जा सकता है

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट (लोक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला) की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर और अन्य ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। लोक अदालत ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2023 को वहां सड़क निर्माण का आदेश दिया था। अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उस आदेश की पालना नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की और स्थायी लोक अदालत की डिक्री (फैसले) की पालना करवाने की मांग की।

जिला न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब सिविल न्यायाधीश ने चारों जिम्मेदार अधिकारियों ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ और जिला कलैक्टर जोधपुर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अप्रार्थीगणों (अधिकारियों) की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी वारंट जारी कर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org
क्रमांक : निविजा/2025-26/ई -32 दिनांक :- 16.12.2025
(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 32/2025-26
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 58.12 लाख के कुल 03 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 16.12.2025 एवं अंतिम तिथि 29.12.2025 तथा निविदा खुलने की तिथी 30.12.2025 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2526WSOB00124
अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/15961

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.
गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर
टैलीफोन नम्बर - 01462-230051 ई-मेल :- npvijaynagar@gmail.com
ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-26
नगर पालिका बिजयनगर द्वारा राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से सिविल कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रीया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। ऑन लाईन निविदा सूचना संख्या 24/2025-2026 के कार्य संख्या 01 से 02 की अनुमानित लागत 47.05 लाख है। ऑन लाईन निविदाए दिनांक 15-12-2025 से 26-12-2025 समय सांय 6:00 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 29-12-2025 को निविदा शुल्क, अमानत राशि एंव प्रोसेसिंग शुल्क की UTR Receipt भौतिक रूप से समय 12:00 PM तक कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। ऑन लाईन निविदा की ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक 30-12-2025 समय प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी। अधिक जानकारी वेबसाईट https://sppp.raj.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
UNB Reference No:- DLB2526A9096
राज.संवाद/सी/25/15916
अधिशाषी अधिकारी

अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, दो शातिर गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर समेत दो शातिर तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मुख्य आरोपियों की पहचान ललित सीरवी और दिलजीत पूनिया के रूप में हुई है। ये दोनों जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे।

एएसपी भोपालसिंह लखावत ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार पुलिस अवैध हथियारों को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम को अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर टीम ने सी अन्नराज सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार और थानाधिकारी बिलाड़ा सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने बिलाड़ा बाईपास के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्यप्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर लाए थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी इन हथियारों को कहां काम लेने वाले थे। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार तस्करी को लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ललित सीरवी निवासी खारिया मीठापुर, दिलजीत जाट निवासी पिचियाक को गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए गए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे।

- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल, पांच मैगजीन, पांच कारतूस और 1.48 लाख रुपए नकद बरामद किए
- दोनों आरोपी जयपुर-जोधपुर हाईवे पर बिलाड़ा बाईपास के पास हथियारों की डील करने पहुंचे थे
- पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से मंगाए थे और किन-किन को सप्लाई किए जाने थे

बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा

मांगरोल, (निसं)। मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव रिंझियां में बेटे ने अपने पिता को धारदार कुठे (एक हथियार) से मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों की सूचना पर मांगरोल थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की लाश को अपने कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां शव को मोर्चरी में रखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड बैठाकर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर सोभाग मल मीणा, डॉक्टर आर बी मीणा व अन्य डॉक्टर के साथ मिलकर शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। अंता डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आढा ने बताया गया कि गृह क्लेस के चलते आए दिन झगड़ा के कारण बेटे ने पिता पर कुठे से हमला कर सिर, पेट व एक हाथ का पंजा काट दिया, जिससे घटना स्थल पर नरोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र सूरजमल निवासी रिंझियां की मौत हो गई। मृतक ने पहले वाली पत्नी को छोड़कर सहरिया जाति की औरत से शादी कर रखी थी, सहरिया औरत के साथ गांव ब्रह्मपुर रामगढ के पास थाना किशनगंज क्षेत्र में रहते थे। कभी-कभी अपने गांव रिंझियां आया करता था। मृतक नरोत्तम की पत्नी सरोज सहरिया ने हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुलजिम विजय नागर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया।

राजस्थान युवा बोर्ड
(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489
क्रमांक :- F.01(15)RYB/2025-26/00021-7863630 जयपुर, दिनांक :- 15/12/2025
शुद्धि पत्र संख्या - 1
"राजस्थान युवा महोत्सव" का भव्य एवं सफल आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजमेंट (EVENT MANAGEMENT) के सम्पूर्ण कार्य हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मों/संस्था/कंम्पनी से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26, दिनांक 15.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन कर दिनांक 18.12.2025 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है। संशोधन का पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.youthboard.rajasthan.gov.in एवं लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
राज.संवाद/सी/25/15928
सदस्य सचिव

किसान महापंचायत में एथेनॉल फैक्टरी हटने तक आन्दोलन जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़, (निसं)। जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने फैक्टरी हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि समय आने पर यही काम आएंगे। महापंचायत में राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन से दो घंटे चली बातचीत के बाद आज की महापंचायत को संपन्न कर दिया। अब सात जनवरी को संगरिया में महापंचायत होगी।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिब्बी में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्टरी के मामले में कहा जा रहा है कि इससे विकास होगा, नौकरी मिलेगी। कहते हैं कि आप विकास का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यही कहना है कि जहां फैक्टरी लगेगी वहां जमीन, हवा और पानी दूषित होगा। फैक्टरी शुरू हो गई तो प्रशासन को दूषित पानी दिखाते रहना। ये 14 फैक्टरी के बराबर है, इसलिए टिब्बी की संघर्ष कमेटी जो फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसा मामला हुआ। मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा की जमीन हाईवे के रास्ते में आ रही थी। वहां झंडा लगा दिया। सरकार को सड़क का रास्ता बदलना पड़ा। यहां भी झंडा गाड़ दो कि एक किलोमीटर के घेरे में जो ट्रक आएगा वो वापिस नहीं जाएगा। ट्रक नहीं आएगा तो फैक्टरी का सामान कहां जाएगा। टिकैत ने कहा कि प्रशासन 144 लगाता है तो किसान भी उससे दोगुनी धारा लगाएगा। अब फैसला संघर्ष समिति को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कमेटी के साथ है। अभी तो बीज कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार जमीन छीनना चाहती है। परिवारों को सरकार बांट रही है। इसके खिलाफ लड़ना है। यहां के कलैक्टर ने ट्रैक्टर को हथियार बताया, उनका धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो। आंदोलन में यही काम आएगा। प्रशासन भले ही रोके लेकिन जहां जाओ ट्रैक्टर लेकर जाओ। आंदोलन में तो ट्रैक्टर जरूर लेकर जाना।

- जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्टरी के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर हमला बोला
- ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, अब सात जनवरी को संगरिया में जुटेंगे : किसान नेता राकेश टिकैत
- टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया

वहीं किसानों ने एथेनॉल फैक्टरी हटाने और 10 व 11 दिसंबर को दर्ज हुए मुकदमे रद्द करने की मांग की। इसी बीच, बुधवार सुबह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक आदेश सार्वजनिक किया गया। इस आदेश के अनुसार, टिब्बी की एथेनॉल फैक्टरी से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बीकानेर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलैक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धान मंडी के मुख्य गेट को छोड़कर अन्य सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके आगे ट्रॉलियां लगाई गई। टिब्बी की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कलैक्ट्रेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है। कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

चढूनी ने कहा कि किसान मुकदमों से डरने वाला नहीं है। यहां की कमेटी जो निर्णय लेगी वहीं लागू होगा। पूरे देश का किसान यहां के लोगों के साथ खड़ा होगा। सरकार को साफ बताना चाहते हैं कि फैक्टरी बंद करनी है तो मतलब बंद कर दो। किसान की बात हल्के में मत लेना। मुकदमे रद्द कर दो, अगर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन हरियाणा में भी होगा। उगराहा ने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा, जब एथेनॉल फैक्टरी हटेगी। पहले सरकार आम आदमी की शिक्षा, रोजगार छीन रही थी। अब बात जमीन, पानी और हवा तक आ गई। एथेनॉल जैसी फैक्ट्रियों से यह सब दूषित हो गया तो आम आदमी कहां जाएगा।

पांच हजार की रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की श्रीगंगानगर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी उसकी माता के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी माता जी के नाम चक 3 एलजीडब्ल्यू तथा चक 1 पीबीएन की जरिये वैयनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में महिला पटवारी ममता ने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा 5 हजार रुपये रिश्वत के पूर्व में ले लिये। अब शेष 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी ममता को पांच हजार रुपये बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/217 - 219 Date :- 12/12/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 63/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत	: रूपये 248.87 लाख (09 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/ अपलोड करने की अवधि	: 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	: 16.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2026 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	: 02.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : ITU2526WSOB00357 To ITU2526WSOB00365
अधिशाषी अभियन्ता - प्रथम
उदयपुर विकास प्राधिकरण
राज.संवाद/सी/25/15921

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL RAJSAMAND
Zila Parishad Road, Rajnagar, Rajsamand Pin 313324
Email :- rajsamandnagarpalika@gmail.com Telephone No. 02952-220034
S. No. F ( )/MCR/Processing Plant/RFP/2025/7702 Date :- 11.12.2025
Corrigendum-I
Technical and financial bids in signle stage two envelops un conditional sealed bid has been invited by Municipal Council Rajsamand to vide SN. 6422 Dated 07-11-2025 submission dated 12-12-2025 at 06:00 PM UBN No. DLB2526WLOB23741 for Design, construction, establishment and development of processing plant and required development work and maintenance of Engineered sanitary landfill site and o&m the 20 years having a minimum adequate capacity for Rajsamand and scalable further as per requirement on VGF basis. The date & time are hereby revised as details below.
Schedule of Bidding Process

Important Events	पूर्वानुसार तिथि व समय	संशोधित तिथि व समय
Estimated Cost	680.00	680.00
Publishing Date & Time	11.11.2025 at 06:00 PM	11.11.2025 at 06:00 PM
Bid Download start Date & Time	12.11.2025 at 09:00 AM	12.11.2025 at 09:00 AM
Bid submission End Date & Time	11.12.2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in	23-12-2025 at 06:00 PM on http://eproc.rajasthan.gov.in
Physically Document Submission Date & Time	12.12.2025 at 01:00 PM	24-12-2025 at 01:00 PM
Technical Bid Opening Date & Time	12.12.2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand	24-12-2025 at 04:00 PM at ULB Rajsamand

Details may be seen at the state public procurement portal http//www.sppp.rajasthan.gov.in, http//www.eproc.rajasthan.gov.in in and may be downloaded from these website.
Commissioner
Municipal Council Rajsamand
Raj.Samwad/C/25/15986

'रेलवे ग्रुप-डी' भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में हो चुका है शामिल

आरोपी ऋषभ रंजन

आरोपी गौत्तम कुमार उर्फ गोटी

- एक भर्ती परीक्षा के लिए 30 हजार रु. एडवांस व परीक्षा के बाद सवा लाख रुपए वसूलता था डमी कैंडिडेट
- पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 31250 रुपए बरामद किए, अन्य लोगों के बारे में पूछताछ जारी

जयपुर (कासं)। जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) जयपुर दक्षिण और सांगानेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट ऋषभ उर्फ रिषभ रंजन और उसका सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और यूपी में करीब दस भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुके है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त गौतम कुमार उर्फ गोटी एक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के लिए तीस हजार रुपए एडवांस एवं परीक्षा के बाद सवा लाख रुपए लेता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी गौतम कुमार के पास से 31 हजार 250 रुपए भी बरामद किए है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि प्रतीक शर्मा ने 10 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज कराया था कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा का सेंटर सीतापुरा में आया था। जहां पर आरोपी ऋषभ रंजन उर्फ रिषभ रंजन (27) निवासी बिहार डमी अभ्यर्थी बनकर के मूल अभ्यर्थी अभिषेक मीना के लिए उसका एडमिट कार्ड व दस्तावेज लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचा।

जिसके चेहरे बॉयोमैट्रिक के स्कैन के दौरान उसका चेहरा मैच नहीं हुआ और वह भी पकड़ा गया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी ऋषभ रंजन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी ऋषभ रंजन का सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी (28) निवासी बिहार ने भी पूर्व में कानपुर,प्रयागराज में इस तरह से फर्जी पेपर दिए थे। पुलिस ने गौतम कुमार को भी दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित ऋषभ रंजन को न्यायालय में पेश कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

वहीं सह आरोपित गौतम कुमार से पूछताछ जारी है। पुलिस ने गौतम कुमार उर्फ गोटी को तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना पर कानोता से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गौतम कुमार डमी छात्र तैयार कर पेपर दिलाने का काम करता है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपी से जयपुर में कहां-कहां और कब-कब परीक्षा में तथा किस के सहयोग से छात्रों के जगह किस परीक्षा में डमी छात्र बैठाए और किस के सहयोग से डमी कैंडिडेट बैठाने का काम किया। इस मामले में पुलिस गहनता से पूछताछ करने में जुटी है।

जेड आकार के प्रस्तावित आरओबी पर जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बांदीकुई के आगरा फाटक पर जेड आकार का आरओबी बनाए जाने से जुडे मामले में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जीएम, डीआरएम, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव, और दौसा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश निखिल झालानी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना इस आरओबी के निर्माण पर रोक लगा दी जाए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने अदालत को बताया कि बांदीकुई में रेलवे फाटक नंबर 104 पर आरओबी बनाया जाने वाला है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब 150 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है। याचिका में कहा गया कि यह आरओबी जेड आकार में बनाया जाएगा। इस आरओबी पर दो जगह तीखे घुमाव होने के कारण यह वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। तीखे मोड से वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहन को देखने में समस्या होगी और ब्रेकिंग के लिए भी कम समय मिलेगा। याचिका में कहा गया कि पूर्व में इंदौर और भोपाल में एल आकार में बनाए गए पुल के कारण वाहन चालकों को समस्या हो रही है। ऐसे में यहां बनने वाले आरओबी पर भी वाहन चालकों को इसी समस्या का सामना करना पडेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से विभागों को कई बार अभ्यावेदन देकर शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी

- उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 के विशेष शिक्षा लेवल-2 में सामान्य शिक्षा में बी.एड और आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों का मामला
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए अभ्यर्थियों को 2 माह में नियुक्तियां देने का आदेश दिया

जयपुर (कासं)। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 के विशेष शिक्षा लेवल-2 में सामान्य शिक्षा में बी.एड और भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (1 वर्ष) रखने वाले अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। जबकि उच्चतम न्यायालय और उससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट भी इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दे चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार कोर्ट में याचिका दायर करने वाले इन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने के बजाय इधर-उधर घुमा रही है। जबकि सामान्य बीएड और डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) वाले कुछ अभ्यर्थियों अल्का डुकिया, प्रशांत कुमार, राधा आर्य, संदीप कुमार समेत कई लोगों को वर्ष 2023 में ही नियुक्तियां दे दी गई थी। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और मनीष शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा है कि, इन सभी अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर तवज्जो दी जाए और 2 माह में नियुक्तियां दी जाए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में जब कुछ अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं दी तो उन्होंने 1 मई 2024 और 12 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की। दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। राज्य सरकार ने इस प्रकरण में "नो अपील" का निर्णय लिया और आध्यापक आदेश जारी कर इन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया। जबकि भर्ती विज्ञापन में योग्यता के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश थे।

सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां 3 नवंबर 2025 को शीर्ष अदालत ने आदेश दिए कि 2 माह के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। परंतु इस आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में पीड़ित अभ्यर्थी राजाराम, हेमलता पूनिया, टीना, अमोल, सीमा, ओमप्रकाश और अन्य को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से अवगत कराया। इसमें कहा गया है कि, याचिकाकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता जो आर.सी.आई. के मुताबिक उपयुक्त है और नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा भी स्वीकार्य की गई है। इसलिए ये सभी अभ्यर्थी विशेष शिक्षा के तहत सफल अभ्यर्थी माने जाएंगे। इस पर खंडपीठ ने भी राज्य सरकार को आदेश दिए है कि 2 माह में इन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाए।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि, जब भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के अधीन थी, तब भी राज्य सरकार ने अदालत के निर्णय का इंतजार किए बिना ही मैरिट से नीचे वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसे संघर्षरत अभ्यर्थियों ने कोर्ट से स्टे लाकर रोका था। इस पूरे प्रकरण के बीच में राज्य सरकार द्वारा इन अभ्यर्थियों के समान योग्यता रखने वाली एक अन्य अभ्यर्थी मीना शर्मा को नियुक्ति दे दी। यह नियुक्ति भी संघर्षरत अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपील "राजाराम बनाम राजस्थान सरकार" के आधार पर दी गई, परंतु कोर्ट में संघर्षरत अभ्यर्थियों से सरकारी महकमा भेदभावपूर्ण व्यवहार करता रहा।

अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करते हुए रिवाइज्ड परीक्षा परिणाम जारी करके सामान्य बी.एड तथा डिप्लोमा (विशेष) वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए समानता का व्यवहार किया जाए।

पीसीएम मसाला टीम ने सहकारिता मंत्री को दी जन्मदिन की बधाई

जयपुर। पिंक सिटी मिल्स (पीसीएम मसाला) की टीम ने सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक के जन्मदिन के पर जयपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी।

पीसीएम मसाला टीम ने सहकारिता मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी।

इस अवसर पर पीसीएम मसाला के प्रबंध निदेशक एल.एल. गुप्ता एवं कृष्ण अवतार खंडेलवाल ने मंत्री को कंपनी की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि पिंक सिटी मिल्स पिछले 56 वर्षों से राजस्थान की अग्रणी एगमार्क प्रमाणित मसाला कंपनी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। कंपनी 70 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं का विश्वास जीतती आ रही है।

पीसीएम मसाला के निदेशक अमित खंडेलवाल एवं अंकित खंडेलवालने मंत्री को जानकारी दी कि कंपनी के दो आधुनिक उत्पादन संयंत्र हैं तथा झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी का स्वयं का कोल्ड स्टोरेज भी स्थित है, जो गुणवत्ता एवं भंडारण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाता है। मंत्री गौतम दक ने पिंक सिटी मिल्स की समृद्ध विरासत, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता एवं निरंतर प्रगति की सराहना की और कंपनी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

हरिदेव जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वर्गीय हरिदेव जोशी राजस्थान की राजनीति के एक सशक्त स्तंभ और अनुभवी जननेता थे। जोशी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करते हुए जनकल्याण, प्रशासनिक सुदृढ़ता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त आधार प्रदान किया। स्वर्गीय हरिदेव जोशी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक, 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक तथा 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक रहा। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, स्वर्गीय जोशी के परिजन मौजूद थे।

'2 वर्ष में 7900 गांवों में जोड़े 13.78 लाख नल कनेक्शन'

जयपुर (कासं)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को जल भवन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वर्तमान सरकार के 2 साल के सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व पर आभार व्यक्त किया।

चौधरी ने कहा कि गत 2 वर्ष में हमारी सरकार ने 4000 गांव प्रति वर्ष अनुसार 2 वर्ष में ही 7 हजार 900 से अधिक गांवों में 13.78 लाख कनेक्शन दिए है। इन पर प्रति वर्ष 5300 करोड़ रुपए के अनुसार 10612 करोड़ रुपए व्यय हुआ। उन्होंने कहा कि शेष कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है, आगामी दो वर्षों में सभी कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में जल उपलब्धता के लिए वर्षों से अटकी ईआरसीपी परियोजना को हमारी सरकार ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में प्रथम चरण के अंतर्गत 9400 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर निर्माण प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त राम जल सेतु लिंक परियोजना में 14676 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुके है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना में 4 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई और 17 जिलो की लगभग 3 करोड़ आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।

सार-समाचार

विधानसभाध्यक्ष का अभिनन्दन किया

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बुधवार को विधान सभा में उदयपुर की स्वंयसेवी संस्थाओं ने मेवाडी पगडी व दुपट्टा पहनाकर, शॉल ओढाकर और आकाशीय अभिनन्दन पत्र भेंट कर अभिनन्दन किया। अभिनन्दन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधान सभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ और अजमेर उत्तर से 2003 से लगातार विधायक पद पर निर्वाचित होने का रिकार्ड हासिल करने वाले शिक्षाविद, मंगलमैत्री के अनुयायी, करुणा के सागर, सामाजिक कार्यो के प्रणेता, वाक शैली और बुद्धि चातुर्य के पर्याय, सेवा व कर्तव्य के आयाम स्थापित करने वाले राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर और सहज, सौम्य व्यक्तित्व व गहन चिन्तन के कीर्ति स्तम्भ है। स्पीकर देवनानी ने वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान, उदयपुर को वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए मिले लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स का अवलोकन किया। देवनानी ने संस्था को मिले इस पुरस्कार के लिए संस्था पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देवनानी ने मनोहर लाल व्यास, गोपेश शर्मा, यशवन्त त्रिवेदी और नीलेश पालीवाल को वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए मेवाडी पगडी और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम शहीदों और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की वीरगाथा को 21 हजार फीट लंबी कपडे की पट्टी पर उकेरने वाले उदयपुर के मनोज आंचलिया और सीमा वेद को भी मेवाडी पगडी और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया।

ड्रामा नाटक "अलबेला गांव" प्रस्तुत

जयपुर। क्यूरियो का "फन-गामा" बाल-किशोर नाट्योत्सव में बुधवार को कला-संस्कृति, पुरातत्व विभाग और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से थिएटर इन एजुकेशन में संस्कृत, जिब्रिश भाषा पर बेस्ड कॉमेडी ड्रामा "अलबेला गांव" का रविन्द्र मंच पर मंचन हुआ। इसका निर्देशन समर्थ शांडिल्य ने किया है, क्रिएटिव आशीष मिश्रा, शवाना खान का है और प्रोडक्शन डायरेक्टर गगन मिश्रा रहे। इस नाटक का आज फ़ीर मंचन हुआ। इसमें पहले पिंक फेस्ट और भटिंडा में इसका बहुत कमाल का मंचन हो चुका है और थिएटर इन एजुकेशन जोन के लिए ये ड्रामा सभी तरह के दर्शकों के लिए बहुत ही क्रिएटिव सराहना पा चुका है।

जयपुर म्यूज़िक स्टेज 15 से 17 तक

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल के साथ-साथ आयोजित होने वाला जयपुर म्यूज़िक स्टेज 15 से 17 जनवरी 2026 तक होगा। इस कार्यक्रम में आज के दौर के संगीत-जगत के चर्चित कलाकारों, इंडी-म्यूज़िक के लोकप्रिय नामों और विभिन्न शैलियों को मिलाने वाले प्रभावशाली समूहों के साथ एक रंगीन और शानदार संगीत-श्रृंखला प्रस्तुत होगी। जयपुर म्यूज़िक स्टेज के फ़ेस्टिवल प्रोड्यूसर अविक रॉय ने बताया कि होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित यह मंच भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत आयोजनों में से एक बन चुका है, जो देशभर की विविध ध्वनियों, कलाकारों की अविस्मरणीय लाइव प्रस्तुतियों को एक साथ लाता है। जयपुर म्यूज़िक स्टेज का शुभारंभ 15 जनवरी को सौमिक दत्ता, ट्रैवलर्स से होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सरोद वादक और वर्ष 2025 के ईस्टर्न आई एक्स्ट्रा अवॉर्ड फ़ॉर म्यूज़िक के विजेता सौमिक दत्ता की एक नई और बेहद ख़ूबसूरत संगीत का माहौल रचने वाली प्रस्तुति है। 16 जनवरी को प्रशंसित रॉक बैंड परवाज़ अपनी विशिष्ट प्रोग्रेसिव और साइकेडेलिक रॉक शैली के साथ इस शाम का प्रमुख आकर्षण होगा। फ़ेस्टिवल का समापन 17 जनवरी को एक रोमांचक और ऊर्जावान फ़िनाले के साथ होगा, जिसका नेतृत्व बहुचर्चित बहु-शैली संगीत समूह थैंक्कुडम ब्रिज करेगा।

जेल निरीक्षण रिपोर्ट की सुनवाई 7 को

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण से जुडे मामले में पूर्व में दिए निर्देश के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की निरीक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए मामले की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि गत 18 अगस्त को अदालत ने सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखे की जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं। इस संबंध में संबंधित जिला न्यायाधीशों की ओर से पेश रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। इस पर अदालत ने कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड पर भी नहीं आई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है। गौरतलब है कि कैदियों के हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सालों पहले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए थे। वहीं बाद में राज्य सरकार ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी पालना रिपोर्ट मांगी थी।

सूरतगढ़-गंगानगर नेशनल हाईवे फोरलेन का होगा

- 75.5 किमी नेशनल हाईवे को फोरलेन करने के लिए 1023 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर (कासं)। भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़- गंगानगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) को टू लेन से फोरलेन करने की स्वीकृति प्रदान की है। एनएच (62) के 75.5 किमी लंबाई की सड़क के फोरलेनकरण के लिए, केंद्रीय मंत्रालय ने 1022.57 करोड़ रुपए की राशी की स्वीकृति प्रदान की है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस हाईवे के फोरलेन निर्माण से द्रुत एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सडक के फोरलेन निर्माण से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा की इससे क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास को नई दिशा एवं गति मिलेगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को उपजों की बडे बाजारों तक पहुँच आसान होगी जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा है की मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में मजबूत आधारभूत ढाँचा स्थापित किया जा रहा है , जो प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रूफ टॉप सोलर लगाने वालों को 17 हजार रु. सब्सिडी

जयपुर। विद्युत वितरण निगमों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना में अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की राज्य सब्सिडी हस्तांतरित करना प्रारंभ कर दिया है। फिलहाल जयपुर विद्युत वितरण निगम ने इसकी शुरूआत की है। इस प्रक्रिया में 169 लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जयपुर डिस्कॉम ने राज्य सब्सिडी के रूप में कुल 28 लाख 73 हजार रुपए हस्तांतरित कर दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि राज्य सब्सिडी की यह राशि पीएम सूर्यघर योजना में देय अधिकतम 78 हजार रुपए की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है। 2 माह में 2.46 हजार लाख उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है।

25 हजार रु. के लिए पडौसी की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय, क्रम 4 महानगर द्वितीय ने 25 हजार रुपए के लिए पडोसी किराएदार की हत्या करने वाले अभियुक्त विक्रांत कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी नीलम करवा ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर हरियाणा की पुलिस में गार्ड का काम करने वाले अमरजीत ने 22 जुलाई, 2022 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता सुभाष यादव एक फुटवियर फैक्ट्री से रिटायर होकर उसके साले के साथ किराए से रहते हैं। तीन दिन पहले उसके साले ने फोन पर जानकारी दी कि उसके पिता घर से बैंक जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। इस पर वह 20 जुलाई को आया और पिता की तलाश की। इस दौरान बैंक के सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिली की पिता के साथ पास के कमरे का किराएदार विक्रांत भी था। जब उसने विक्रांत से इस बारे में पूछा तो उसने बैंक जाने से मना कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर शव को पास के जंगल स्थित नाले से बरामद किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त बैंक से सुभाष को नाले में ले गया था और मौका देखकर भारी पत्थर से सिर पर वारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की जेब में रखे 25 हजार रुपए लेकर चला गया। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और बैंक से रुपए निकालने की जानकारी मृतक के रिश्तेदार को थी।

"सुपर से ऊपर" ब्रांड का 1411 किलो वेजिटेबल सॉस जब्त

जयपुर। प्रदेश में चल रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कानोता स्थित 'सुपर से ऊपर' ब्रांड के वेजिटेबल सॉस बनाने वाली फर्म मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज पर बड़ी कार्रवाई की है। फर्म द्वारा निर्मित वेजिटेबल सॉस की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों और पूर्व जांच रिपोर्ट्स के आधार पर यह छापेमारी की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि वेजिटेबल सॉस की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूनिट पर फूड लाइसेंस तो पाया गया, लेकिन नियमानुसार उसे प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके अलावा फर्म संचालक न तो पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सके और न ही उत्पादन में उपयोग किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। यूनिट में कार्यरत फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौके पर नहीं मिले। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में साफ-सफाई की स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर फर्म को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मौके पर करीब 1411 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस तैयार अवस्था में पैक किया हुआ मिला, जिसे बाजार में बिक्री के लिए भेजने की तैयारी थी। टीम ने सैंपल लेकर पूरे माल को मौके पर ही सीज कर दिया। कार्रवाई के समय फर्म संचालक तीर्थराज शर्मा मौके पर मौजूद रहे। विभाग ने बताया कि इस फर्म के खिलाफ पूर्व में भी एफएसएसएस एक्ट के तहत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। लिए गए नमूनों को जांच के लिए केंद्रीय,राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेशचंद यादव, अवधेश गुप्ता और नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।

राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम साबित होगी गेम चेंजर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से हरित भविष्य की दिशा में बढ़ रहा राजस्थान

जयपुर। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके दुष्प्रभाव जल, थल और नभ के माध्यम से न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण जैव विविधता और अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में हरित विकास को प्राथमिकता देना एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को केंद्र में रखते हुए ऐसे दूरदर्शी कदम उठाए हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर कल देने की दिशा में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस साल लाए गए ग्रीन बजट की बजट घोषणा की अनुपालना में विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी की गई राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025, राज्य को यूज एण्ड डिस्पोज की प्रवृत्ति से निकालकर रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य वेस्ट टू वेल्थ यानी अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हो सकें।

इस योजना के अंतर्गत रिसाइक्लिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग, ई-वेस्ट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, वाहन स्क्रैपिंग, पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्योगों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, बैटरी, टायर, टेक्सटाइल, रबर, कागज, धातु रिसाइक्लिंग से संबंधित इकाइयों, कृषि अवशेषों, जैव अपशिष्ट, निर्माण मलबे तथा औद्योगिक अपशिष्ट का प्रोसेसिंग कर उपयोगी उत्पाद या ऊर्जा तैयार करने वाली इकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स और एमएसएमई द्वारा विकसित क्लीन-टेक, ग्रीन-टेक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन, रिपेयर-रिफर्बिश और रिसोर्स रिकवरी से जुड़ी नवाचार परियोजनाओं को भी इस योजना में शामिल की गई हैं। कम्पोस्टिंग, बायोगैस प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी आदि से जुड़ी नवाचार आधारित मशीनरी और टेक्नोलॉजी के निर्माण की इकाइयों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। वेस्ट टू वेल्थ पार्क (सर्कुलैरिटी पार्क) से अपशिष्ट प्रबंधन को संगठित स्वरूप मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य का पहला 'ग्रीन बजट' प्रस्तुत किया। 27 हजार 854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज एडप्टेशन प्लान-2030 तैयार करने, 150 करोड़ रुपए की लागत से जलवायु परिवर्तन पर उत्कृष्टता केंद्र, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधारोपण, 4,700 से अधिक गांवों में जल संग्रहण संरचनाएं तथा ग्रीन अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान जैसी घोषणाएं की गई।

ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सभी सरकारी कार्यालयों एवं पीएचईडी पंपिंग स्टेशनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने, सोलर दीदी कैडर, नि:शुल्क इंडक्शन कुकटॉप, बैटरी चलित सार्वजनिक परिवहन तथा ग्रीन ऑडिट आदि से जुड़ी घोषणाएं भी इसमें की गई।

इसके साथ ही वाहन स्क्रैप नीति, प्रत्येक पंचायत में बर्तन बैंक, क्लीन एण्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर, ग्रीन चैलेंज फण्ड और ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म जैसी नवाचारपूर्ण योजनाएं भी ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान और मिशन हरियालो राजस्थान में दो वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगवाए हैं और 14,500 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है।

Bake Cookies Day: A Sweet Celebration of Warmth and Tradition

Bake Cookies Day, celebrated on December 18, invites people to embrace the joy of homemade treats and the timeless comfort of baking. The day encourages families and friends to come together in the kitchen, creating delicious cookies that fill homes with warmth and festive aromas. It highlights the simple pleasure of sharing freshly baked treats, whether classic chocolate chip, spiced gingerbread, or creative new recipes. Beyond its culinary charm, Bake Cookies Day celebrates togetherness, creativity, and the small traditions that make the holiday season special. It's a reminder that sometimes, the sweetest memories begin with a warm oven and shared moments.

#TRENDS

The Exoticism of the East

The Exoticism of the East: A Cultural Obsession That Transformed French Jewellery and Fashion

At the turn of the 20th century, Paris became the nexus of a cultural phenomenon that captivated designers, artists, and society at large: the 'exoticism of the East.' This fascination wasn't just an aesthetic trend; it was a cultural obsession that reshaped the language of jewellery and fashion, influencing the design ethos of the era. From the ateliers of Place Vendôme to the maison collections of the Belle Époque, the allure of Eastern culture permeated the Parisian fashion scene. As global travel expanded, and colonial exhibitions brought the wonders of India, Persia, China, and Japan to Paris, the East left an indelible mark on Western art, transforming jewellery design into a cross-cultural conversation.

1. The Role of Colonial Exhibitions and Global Exploration

The dawn of the 20th century saw the height of the European colonial empires, which led to a surge in global exploration and cultural exchange. The Exposition Universelle of 1900 in Paris was a particularly pivotal moment, showcasing the wealth of Eastern art, culture, and craftsmanship. The exhibitions brought in treasures from India, Persia, China, and Japan, creating a new level of exposure to foreign objects, gemstones, and textiles that had previously been beyond European imagination.

2. The Eastern Aesthetic: India, Persia, China, and Japan

Each Eastern culture offered a unique aesthetic that inspired French jewellers in different ways:

- **India:** India, with its long history of gemstone cutting, kundan (gold setting), and meenakari (enamel work), captivated designers like Cartier. The country's rich gemstone palette, rubies, emeralds, and sapphires, inspired pieces of jewellery that combined bright, bold colours with intricate designs.
- **Persia:** Persian design, known for its geometrical patterns and delicate motifs, had a profound impact on the Art Deco movement. Persian arts' focus on symmetry and ornamental motifs translated into jewellery designs that often featured intricate engravings and stone settings.
- **China:** China's contribution to Western jewellery came in the form of jade, lacquer, and porcelain. Known for its association with immortality and purity, jade became a highly prized material in the making of pendants, bracelets, and rings. Designers were also drawn to the minimalist aesthetic of Chinese art, its elegance, restraint, and symbolism.
- **Japan:** The Japanese aesthetic of simplicity and nature-inspired designs had a profound influence on the early 20th-century jewellery scene. Japan's craftsmanship in lacquerware and textiles was admired for its understated beauty.

3. Curiosity Becomes Fascination: The Reinterpretation of Eastern Elements

What started as curiosity about Eastern culture soon evolved into an intense fascination. Parisian jewellers didn't merely copy the designs and motifs they saw in the exhibitions; they began to reinterpret them, blending Eastern forms with Western craftsmanship. The resulting pieces were a synthesis of the two worlds, leading to some of the most iconic jewellery creations in history. Cartier, in particular, became known for its ability to fuse Eastern aesthetics with French artistry. The Tutti Frutti collection, with its elaborate use of emeralds, rubies, sapphires, and diamonds, is one of the most celebrated examples of this cross-cultural dialogue. Similarly, the geometric designs inspired by Persia's ornamental art found expression in Art Deco jewellery.

4. The Enduring Legacy: Eastern Influence on Modern Jewellery

By the time Art Deco reached its peak in the 1920s and 1930s, the influence of the East had become firmly embedded in Western jewellery design. The techniques and motifs inspired by India, Persia, China, and Japan left a lasting legacy, which can still be seen in the jewellery collections of today's most prestigious houses. The interplay between Eastern and Western aesthetics in jewellery not only transformed the designs of the early 20th century but also established a precedent for global influences in the world of luxury. The elegance of Chinese jade, the richness of Indian gemstones, the precision of Persian geometry, and the simplicity of Japanese forms continue to influence contemporary jewellery, providing a timeless link between cultures.

Plain-bellied Emerald.

Blue and yellow Macaw (Ara ararauna).

Canje Pheasant.

Glittering-throated Emerald Male.

My Bush Hunting Days

Sunsets are different in Guyana where you are almost on the equator, so, there is no twilight. If you are in the Savannah, one minute you see a flaming globe that colors the whole sky, anything from a deep orange to blood red and the horizon looks as if the whole world is on fire. Then, there is sudden darkness. If you are on a trail in the forest or on the river, you will find yourself in darkness, but if you look up at the tops of the trees, you will see bright sunlight, lighting them up. Treetops look like they are on fire and remain that way a long time after darkness has fallen on you.

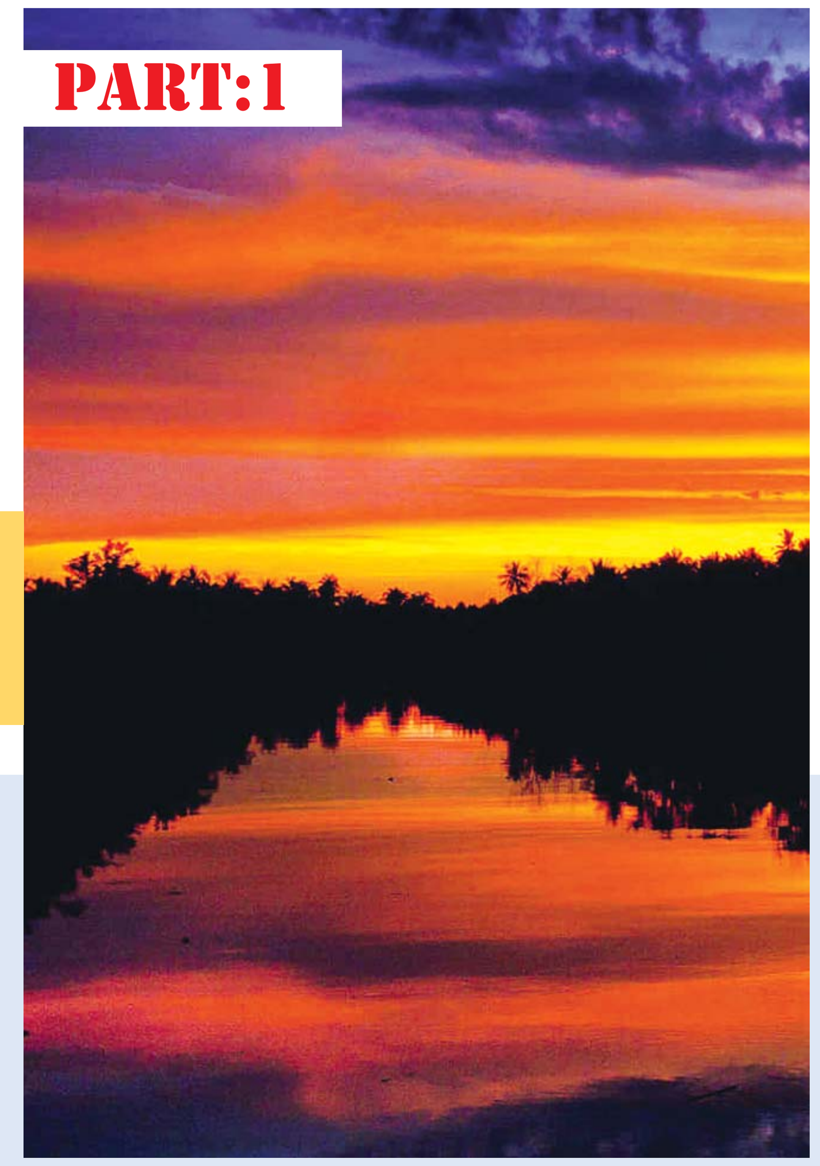

Guyana's sunset reflections.

Mirza Yawar Baig
Naturalist and Wildlife Conservationist

I love the bush and I loved hunting. So, every alternate weekend, Peter Ramsingh and I would go on a long drive into the bush to hunt what we could. Most of this was for the table because in the Kwakwani of those days, if you wanted variety on your table, you had to find it yourself. The Commissary (company owned department store) was no help in adding variety to the table either. My cook and housekeeper, Naomi, was a gem of a woman, very large, very bossy and with a heart of gold. She was from St. Lucia and took it as her bounden duty to fatten me up. But no matter how many delicious meals she cooked, I refused to get fat.

Naomi appreciated getting fresh fish and bush meat to cook. I never asked her to account for what I gave her, which suited us both very well. The last thing I wanted to do was to count pennies and eggs and if she took something for her family, she was most welcome.

Macaw (Ara ararauna).

Naomi took care of my house, cleaning, washing clothes, ironing, and cooking. Everything inside the house. I took care of my pets, poultry, and what garden there was. My hunting and fishing therefore had other beneficiaries.

We hunted mostly birds; the Canje Pheasant found all along the Berbice and its tributary, the Canje Creek. Another common game-bird was the Powis (Curassow). It was as big as a turkey and good eating. We would also, on occasion, get an Agouti (Brazilian Agouti or Red, Orange or Golden Rumped Agouti) or two. And when we were lucky, a small Savannah deer. Bush pig, the Collared Peccary (called Javelina) was also good game, and though we both did not eat it, we had many friends who welcomed our hunts because we were the only people who would shoot a pig and then give it away. I never shot a Tapir or Jaguar or Puma. I never even saw a Jaguar or Puma in all the years I lived in Kwakwani, which is strange, because there are many in those forests. But given the nature of the forest, it is understandable.

Peter inherited my yellow Land Rover when the sawmill started, and I got a small Toyota pickup. Peter and I would take turns driving the Land Rover over the bush trails. The Land Rover contained in the back everything that we needed for our camping or emergencies. A chainsaw, thick rope, hammocks, some fishing net and lines and hooks, jerry cans with spare petrol, an axe, a spade, the ever-present cutlasses (machetes), and various odds and ends. Each of us carried a 16-gauge shotgun. We would load up a cooler filled with drinks and some pre-cooked bananas or cassava and off we would go. What would have been ideal was a cell phone or radio but the first hadn't been invented and the second we didn't have. So, we relied on ourselves.

What we shot, we would cook in the bush and eat. What we saved; we would bring home. Sometimes, in the bush, we would come across a stream flowing at the bottom of a deep ravine and would have to build a bridge to get across it. At other times, we would get stuck in the sandy soil, and if piling freshly cut leaves and branches under the wheels didn't work, we would tie

#AFRICA

Javelina.

Howler Monkey.

Hummingbird.

the rope to a nearby tree and use the winch on the Land Rover to haul it out. In the evening, we would find a camping place, sling our hammocks between ever present trees, all conveniently located so that we could tie our hammocks, of course. Then, we would light a fire and put on the tea pot.

Once we had a nice cup of tea sweetened with condensed milk, we would put on the cooking pot. Peter, meanwhile, would have cleaned the game of the day. We would get water from the stream nearby, water that was coffee colored but perfectly clean and tasteless. The color was due to the dyes that leach into the water from the roots of trees that trail their feet in the stream. I have no idea what those dyes did, but they didn't seem to have any detrimental effect, and we drank that water straight from the stream all the time we were in the bush, with no ill effects. The bush meat would go into the pot with salt and chillies, some onions, and as it cooked, we would sit and talk about life.

Sunsets are different in Guyana where you are almost on the equator, so, there is no twilight. If you are in the Savannah, one minute you see a flaming globe that colors the whole sky, anything from a deep orange to blood red and the horizon looks as if the whole world is on fire. Then, there is sudden darkness. If you are on a trail in the forest or on the river, you will find yourself in darkness, but if you look up at the tops of the trees, you will see bright sunlight, lighting them up. Treetops look like they are on fire and remain that way a long time after darkness has fallen on you.

Travel needs to be planned therefore, so that you don't blunder into a ravine or into something harmful in the dark. As soon as the sun starts to go down, you need to be in your camp with a fire to start your night. Nights tend to be long as there is nothing to do apart from talking to your companions in the firelight, which can be very pleasant depending on the quality of the company, you and your companions. The fire casts strange shadows because of the 'floor level' lighting, illuminating some parts of your face while making others dark. The dancing flames constantly change the pattern of shadows which is fascinating to watch. But looking into a fire, though it is instinctive, destroys your night sight, so, when you look away from it, you are totally blind for a while until your eyes adjust to the darkness. For this reason, when you are in the bush and sitting at your fire, it is better not to look directly at it.

The bush in South America is different from its counterpart in India or Africa, and in my view, less dangerous because of the absence of major predators and large herbivores like rhino, elephant, and hippo. The only big ones are the Jaguar and the Anaconda, but neither will attack a person except in special circumstances. So, it is possible to sleep very peacefully if you are not on the ground.

An hour or so later, once the food was ready, we would take the pot off the fire, pull out the bread that we had brought, and have our dinner. Then, after some more discussion of world affairs, we would climb into our hammocks and drift off into peaceful sleep, looking at the stars, possible only when we were camped at the riverbank where the canopy did not obstruct the view. Those days seem like a dream today. Almost as if they never happened. And Guyana is so far away from where I am today that it seems as if I will never see my friends again. Be that as it may, the memories are alive in my heart and on these pages; they will live on in the minds of those who read this. We live in the memories that we give others. So, it is important to be conscious of the memories we leave behind. This doesn't mean that we live our life for others. But it does mean that we remember one cardinal fact, 'Everything we choose to do or choose not to do reflects brand value and character and is the stuff of memories.'

Remember when you read these pages, that if I have written about a stream, it is there, and the water is good to drink. These are stories of real life, real people, their hopes and loves and fears. And they will live on until they are remembered.

The Berbice River was the lifeline of the forest. If you lived in Kwakwani, no matter where you went in the bush, you were never far from the river. The rainforest was so thick and difficult to traverse that the preferred mode of transportation was by boat on the river. In our case, when we were driving on the Savannah, we were away from the main river, but every so often, we would cross its tributaries, some flowing and some waiting for the rain to flow. Camping near their banks was a risk because what was a dry, sandy stream bed could become a raging torrent in minutes. If that happened in the middle of the night when you were fast asleep in your tent, you could end up losing all your possessions and worse. We ensured that we always camped on the other side of whichever stream we needed to cross and high up above its bank. We would take water from it, bathe in it and enjoy that, but we would sleep away from it.

The water of the Berbice River changed complexion throughout the day. Early in the morning it has, what looks like steam rising from it. So, you would be floating through this cloud of vapor looking ethereal and ghostly. As the sun rose and it got hotter, we were sitting close to the equator, remember, the mist would disappear, and you would see the colors of the trees reflecting in the river. If we were planning to stay another day, we would spend a couple of hours walking in the forest, following some track or the other simply to enjoy the experience of being in the rainforest. We were not hunting seriously and only the unwary animal with suicidal tendencies achieved its objective at our hands.

We were more interested in watching Hummingbirds flit from flower to flower looking like moths more than like birds. Hummingbirds beat their wings so fast that you can't see them, and they are the only birds that can fly backwards. They fly up to a flower, and hovering before it on buzzing wings, insert their specialized beaks deep into it for the nectar, then fly backwards to get out of that flower and go to another one. For those who like details, the wingbeat of Hummingbirds varies from 15-90 beats per second. Yes, per second.

Mornings are announced by the booming call of the Howler Monkey answered by his cousins everywhere, and so for a while, there would be cacophony in the forest. Macaws taking off for their daily commute would also be talking to each other and you would hear their calls. Toucans would call to each other as they hunted for fruit in the tops of giant figs. You would hear the crash of branches as Sakiwinki (Spider Monkeys) took off on their highway a hundred feet in the air, throwing themselves from one forest giant to another with gay abandon.

They would be followed by others, heavier than them and the branches would crash more loudly. Ah! The difficulty is in trying to describe what the eye sees, what the ears hear and what the heart feels in mere words on paper. It is the whole atmosphere of the forest when you become one with it, when time has no meaning and the daily grind and work pressure feel like a bad dream that you woke up from.

In Guyana, I never heard the term 'rainforest.' People used 'backdam' or just 'bush.' Even 'forest' was not used, though, we lived in the middle of it. These lands were not truly uncharted because people, mostly Amerindian hunters, and loggers, had long gone along the trails that we drove on. I have no idea who made these trails originally, but they were ideal for Peter's yellow Land Rover. Peter had a great sense of direction, so, we always got back safely two days later, even though, I had no clue where we were going or had been. I would just concentrate on the driving or on watching out for game.

To be continued...

rajeshsharma1049@gmail.com

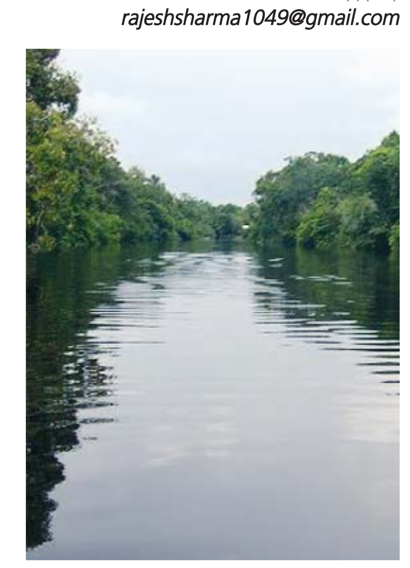

The Berbice River.

#EDMONIA LEWIS

The Trailblazing Sculptor Who Defied Boundaries

Despite facing significant racial prejudice and personal challenges, Edmonia Lewis's work has earned her a lasting legacy in the art world

Edmonia Lewis (1844-1907) stands as one of the most remarkable and pioneering artists in American history. Born to a mixed-race background, of African American and Native American descent, Lewis broke barriers in both race and gender to become the first African American and Native American woman to gain international recognition as a sculptor. Despite facing significant racial prejudice and personal challenges, her work has earned her a lasting legacy in the art world.

Early Life and Education

Edmonia Lewis was born in Greenbush, New York, in 1844, to a father of Haitian descent and a mother who was part Native American. After the death of both of her parents at a young age, Lewis was raised by her maternal relatives, the Chippewa people. Growing up amidst the struggles of racial and cultural tensions, Edmonia's early life was one of resilience.

She initially studied at Oberlin College in Ohio, where she was the subject of both admiration and prejudice. Despite these challenges, she excelled academically and found a passion for art. In 1863, she moved to Boston to pursue her artistic career, but it was in the next phase of her journey that she would find her true calling in sculpture.

Move to Boston and Artistic Development

In Boston, Lewis studied under renowned sculptor and educator Horace Mann and soon gained the attention of the city's art community. Her first major public work, *The Death of Cleopatra* (c. 1876), displayed her exceptional talent in marble sculpture, blending her technical skill with evocative emotion. However, it was the highly detailed realism of her works and her ability to capture powerful themes from African and Native American histories that set her apart from many of her contemporaries.

Her early sculptures featured themes of mythology, history, and portraiture, but it was her focus on creating sculptures of Black and Indigenous subjects that made her stand out in an overwhelmingly Eurocentric art scene.

Paris and International Recognition

In the late 1860s, Lewis moved to Rome, a city that was home to many expatriate artists. There, she found both freedom and opportunity, both in the art world and in society at large. During her time in Europe, she created some of her most iconic works, including *Forever Free* (1867), a sculpture that depicted a Black man and woman breaking their chains of bondage. The piece, a powerful statement on emancipation, garnered much attention and was displayed in major exhibitions, helping to establish her reputation.

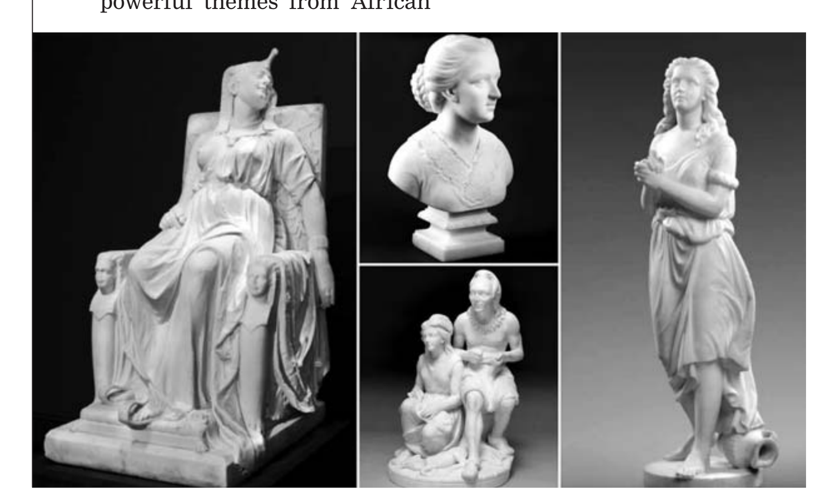

Themes of Race, Identity, and Empowerment

Many of Lewis's works address complex issues of race, freedom, and identity. As an African American and Native American woman in an era of intense racial discrimination and gender inequality, she used her art as a vehicle for social commentary and cultural expression. For example, The Death of Cleopatra (1876) was controversial not only because of its striking realism but also due to the fact that it represented a Black woman as the subject of classical mythology, an unprecedented move at the time.

Legacy and Influence

Despite her trailblazing career, Edmonia Lewis faced numerous obstacles due to her race and gender. She was often excluded from prominent art circles and struggled with both professional and personal setbacks. For instance, she faced criticism for being a woman in a male-dominated field, and her work was sometimes dismissed by critics who were uncomfortable with the themes she explored.

Nevertheless, her influence and reputation grew over time. Today, she is celebrated as one of the most important sculptors in American history. Her works continue to be recognized for their historical significance, their technical skill, and their contributions to the representation of Black and Indigenous peoples in the arts. Edmonia Lewis's commitment to self-expression and social justice has inspired generations of artists, especially those from marginalized communities, to push boundaries and redefine the possibilities of art.

THE WALL

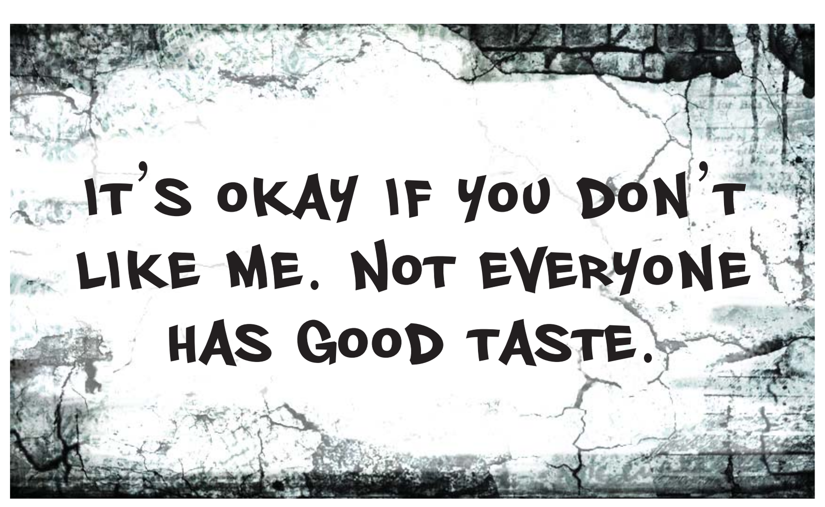

BABY BLUES

By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS

By Jerry Scott & Jim Borgman

मांगलियावास में एलपीजी टैंकर से अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई

एक एलपीजी टैंकर, एक लोडिंग टेंपो सहित 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त

पुलिस ने मांगलियावास थाना क्षेत्र में सराधना स्थित होटल पर टैंकर से सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की।

■ मौके पर एलपीजी गैस टैंकर के माध्यम से सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी

अजमेर, (निसं)। हाईवे स्थित होटलों पर अवैध गैस रिफिलिंग का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी के दिशा-निर्देशों पर अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मांगलियावास थाना क्षेत्र में एनएच-48 पर सराधना स्थित होटल पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक एलपीजी गैस टैंकर, एक लोडिंग टेंपो सहित 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। मामले की सूचना रसद विभाग को भी दे दी गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार गत दिनों भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए एक अन्य होटल से गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त सिलेंडर जब्त किए थे, इसके बावजूद अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं। मांगलियावास थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि सराधना स्थित होटल बालाजी पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देर रात करीब एक बजे मौके पर पहुंचकर दबिश दी। वहां एलपीजी गैस टैंकर के माध्यम से सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से गैस टैंकर को कब्जे में लेते हुए एक लोडिंग टेंपो तथा 45 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गैस कहां से लाई गई थी, किन उपभोक्ताओं या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक इसकी आपूर्ति की जा रही थी तथा इस अवैध धंधे में कितने लोग शामिल हैं।

पिछले दिनों भी हुई थी कार्रवाई :- मांगलियावास थाना क्षेत्र में इससे पहले भी अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद से एनएच-48 पर गैस रिफिलिंग और अवैध भंडारण की गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई थी। हाल ही में एनएच-48 स्थित होटल जयपुर गोल्डन पर जिला स्पेशल टीम ने छापा मारकर बड़े स्तर पर अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण का खुलासा किया था। उस कार्रवाई में दो पिकअप वाहन, एक गैस टैंकर, एक लोडिंग टेंपो, 115 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, एक घरेलू गैस सिलेंडर तथा रिफिलिंग में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अलावा एक पिकअप वाहन में डीजल भी मिला था, जिसे जब्त किया गया।

पुलिस के अनुसार हाईवे किनारे कुछ ढाबों और होटलों की आड़ में गैस रिफिलिंग का संगठित नेटवर्क सक्रिय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध गैस रिफिलिंग से आगजनी और विस्फोट जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बंद मकान के ताले तोड़ चार लाख का सामान चोरी

सांभर में चोरी की वारदात के बाद मकान में सामान बिखरा पड़ा है।

सांभरझील, (निसं)। यहां खटीकों की हथाई के नजदीक बड़ा बाजार स्थित घनी आबादी के बीच बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर चोरों ने करीब चार लाख रुपए के समान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना विनोद साहू पुत्र रामचंद्र साहू के मकान में हुई जो लंबे समय से काम के लिए जयपुर रहते हैं।

परिवार के सदस्य आशीष साहू ने बताया कि हमारी ताई जी पांच-छह रोज में एक बार अपने काम के सिलसिले में सांभर आकर इसी मकान में ठहरती है अपना काम निपटाकर वापस जयपुर चली जाती है। अभी 2 दिन पहले ही सांभर आई थी। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ताला टूटा देखा तो इसकी इत्तला परिवारजन को दी। बताया कि चोर मकान में गेट कूदकर अंदर चले गए और सीढ़ियों का दरवाजा उतार कर अंदर प्रवेश कर गए, जहां नीचे व ऊपर स्थित कमरों का ताला तोड़ा और घर में रखा समान चोरी कर ले गए।

पीड़ित ने बताया कि एक तोला सोने के टॉपिस, 3 पायजेब, 1 सोने का मांडलया, 2 कड़े चांदी के, 1 चांदी की चेन के अलावा 14 हजार नकदी भी चुरा कर ले गए। मकान बंद होने के कारण चोरों ने तसल्ली से सामान को बिखरा और पूजा स्थल में रखी चांदी की गाय की मूर्ति जरूर छोड़ दी, बाकी तीन-चार सिक्के बताए गए हैं वह नहीं मिले। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची लेकिन देर शाम तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आशीष ने बताया कि यह ऐसा घनी आबादी वाला इलाका है जहां तक मेरी जानकारी में है आज तक कभी चोरी नहीं हुई लेकिन यह तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। इससे आसपास के रहने वाले लोगों में अब दहशत पैदा हो गई है।

चोरी की 15 बाइक सहित एक आरोपी गिरफ्तार

प्रताप नगर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी दीपक खटीक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है।

प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी ने 5 नवंबर को सिद्धी प्लाजा गंगापुर चौराहे से मुकेश शर्मा की हीरो स्पेंलडर मोटरसाइकिल चोरी की थी।

पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी दीपक खटीक (20) उर्फ दीपसा निवासी खटीक मोहल्ला, थाना भिनाय, जिला अजमेर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह, आशीष मिश्रा, शंभु लाल और अन्य अधिकारी शामिल थे।

बारां मेडिकल कॉलेज को देहदान मिला

कोटा, (निसं)। बूंदी जिले के एक छोटे से गांव अड़ीला के निवासी और शिक्षाविद् छोटू लाल बाथरा ने अपनी मृत्यु को भी जीवनदान में बदल दिया। उनके पार्थिव शरीर के दान से बारां मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कॉलेज को अपनी स्थापना के बाद पहली बार एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए कैडेवर (पार्थिव देह) प्राप्त हुआ है।

अड़ीला गांव के त्रिमूर्ति बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक छोटू लाल बाथरा का मंगलवार शाम कोटा में आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद शोकाकुल परिवार ने विलाप करने के बजाय उनकी अंतिम इच्छा को सर्वोपरि रखा। कापरेन शाखा के संरक्षक एवं ग्राम विकास प्रोजेक्ट के पूर्व नेशनल सेक्रेट्री ललित कुमार टेलर ने बताया कि बाथरा ने देहदान का संकल्प पत्र भरा था। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए शाईन इंडिया फाउंडेशन के डॉ.कुलवंत गौड़ और कापरेन शाखा ने तत्काल मोर्चा संभाला। पहले कोटा में उनका नेत्रदान संपन्न हुआ और फिर उनकी देह बारां मेडिकल कॉलेज लाई गई।

सड़क हादसे में भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल सहित दो गनमैन घायल

विधायक की कार को प्याज से भरे ट्रक ने साईड से टक्कर मार दी थी

सड़क हादसे में घायल भाजपा विधायक कालूलराम मेघवाल का अस्पताल में उपचार किया।

कोटा, (निसं)। नान्ता थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से झालावाड़ के डग से भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल सहित दो गनमैन सड़क हादसे में घायल हो गये। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक की कार को प्याज से भरे ट्रक ने साईड से टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम एवं पुलिस उपअधीक्षक मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि हादसा नान्ता इलाके में हुआ, भाजपा विधायक की कार को साईड से एमपी नम्बर के ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल विधायक कालूराम मेघवाल और दो गनमैन मनीष और सुरेश को चोटें आई, सभी को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

नान्ता थानाधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि डग विधायक कालूराम मेघवाल दो गनमैन के साथ कार से जयपुर की ओर जा रहे थे, एमपी नम्बर का ट्रक हैंगिग ब्रिज की तरफ जा रहा था, शंभूपुरा तिरोह पर विधायक की कार जैसे ही जयपुर जाने के घूमी तो ट्रक ने कार को साईड से टक्कर मार दी। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में घायल सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मौके से ट्रक को जप्त कर चालक की तलाश जारी है।

आहोर में मुख्यमंत्री की सभा में प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई को नहीं मिली तवज्जो

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में नाराज के.के. विश्नोई गले में काला गमछा पहनकर मंच पर बैठे नजर आये

■ वहीं सीएम के आगमन के चलते आहोर में करोड के भूमि घोटाला की पोल नहीं खुले जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को घर पर ही नजरबंद कर दिया

जालोर, (कासं)। जालोर के निकट आहोर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शहरी व ग्रामीण समस्या समाधान शिविर एवं विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री के. के . विश्नोई को तवज्जो नहीं मिली। वहीं नाराज विश्नोई गले में काला गमछा पहनकर मंच पर बैठे नजर आये। वही सीएम के आगमन के चलते आहोर में करोड के भूमि घोटाला की पोल नहीं खुले जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को घर पर ही नजरबंद कर दिया।

आहोर में मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर इस बार मंच पर भी चुंनिदा नेताओं को ही बैठने दिया गया। प्रभारी मंत्री के .के .विश्नोई का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होने से मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही सम्बोधन के लिए बुलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के बाद किसी प्रकार की कोई तवज्जो नही दी गई। प्रभारी मंत्री को ना तो माला, साफा व किसी प्रकार से स्वागत व सम्बोधन के लिए बुलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रभारी मंत्री से ज्यादा किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं की। वही नाराज प्रभारी मंत्री विश्नोई गले में काला गमछा डाले बैठे रहे, जबकि मुख्यमंत्री की सभा में आने वाले हर व्यक्ति से काली चीज बाहर ही उतरवाई व डलवाई गई। वहीं एक व्यक्ति का काला शर्ट ही उतरवा दिया, वह व्यक्ति बनियान में सभा स्थल पहुंचा। जहां सभा स्थल पर किसी प्रकार की काली वस्तु लेने जाना प्रतिबंधित रखा था, वही दूसरी तरफ प्रभारी मंत्री भाजपा का गमछा गला में डालने की बजाय विरोध का प्रतिक काला गमछा डालकर मंच पर बैठे रहे।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शिव सेना के जिला प्रमुख रुपराज राजपुरोहित को नजरबंद किया गया। शिव सेना जिला प्रमुख रुपराज आहोर में नगरपालिका की सरकार की करोड़ों की भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनके इस मुद्दों को रखने से रोकने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुबह ही रुपराज राजपुरोहित के घर पर पुलिस भेजकर मुख्यमंत्री की सभा में जाने से रोका गया। सीएम की सभा तक रुपराज को घर पर ही पुलिस ने नजरबंद कर रखा। ऐसे में नजरबंद करना लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वही सीएम की सभा में भीड़ लाने के लिए नरेगा श्रमिकों को लाना पड़ा।

वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में जालोर की जीवन रेखा व लम्बे समय से सघंर्ष कर रहे किसानों की मुख्य मांग जवाई बांध पर जालोर का हक तय करने सहित जवाई पुर्नभरण पर किसी प्रकार की बात नहीं कही।

दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी इलाके में झपट्टा मारकर कोचिंग छात्र से मोबाइल छीनने के दर्ज मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को निरूद्ध किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 14 अन्य मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 15 दिसम्बर को महाराष्ट्र हाल लेंडमार्क सिटी निवासी एक कोचिंग छात्र ने कुन्हाड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। कोचिंग छात्र ने रिपोर्ट में कहा कि रूम पर जाते समय रास्ते में पीछे से बाइक पर दो लड़के आये और मोबाइल पर झपट्टा मारकर छीनकर ले गये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी कोचिंग छात्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने घटनास्थल के आस-पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चैक किये। शहर एसपी ने बताया कि टीम ने बापूनगर बालिता रोड़ निवासी विजय (21) एवं बालिता रोड़ कुन्हाड़ी निवासी आकाश अहिरवार (19) को बीमार्ट के पास कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया।

राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं : दिया कुमारी

■ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की

जोधपुर, (कासं)। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई नई नीतियां लागू की हैं, जिससे विकास को गति मिली है। इसका लाभ प्रवासियों को भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रही थी।

उप मुख्यमंत्री ने सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के परिश्रम से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 में विकसित राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दस दिसंबर को मनाए गए प्रवासी राजस्थानी दिवस के बाद अब समय आ गया है कि प्रवासी अपनी मातृभूमि राजस्थान लौटें और यहां निवेश करें। प्रवासियों के निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम के स्वागत में मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा सहित अन्य पदाधिकारी, समाज के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री एयरपोर्ट से मारवाड़ जंक्शन रवाना हुईं, जहां सिरियारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं।

अजमेर : ख्वाजा गरीब के 814वें उर्स की शुरुआत

बुलंद दरवाजे पर अकीदत के साथ उर्स का झंडा चढ़ाया।

■ भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने निभाई परंपरा, चांद दिखाई देने पर छह दिवसीय उर्स की औपचारिक शुरुआत 21 या 22 से होगी

अजमेर, (निसं)। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814 वें सालाना उर्स की औपचारिक शुरुआत बुधवार को दरगाह शरीफ के ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ हुई। यह रस्म सूफी परंपराओं के अनुसार शानो शौकत, अकीदत और रूहानी माहौल में अदा की गई। झंडे की रस्म असर की नमाज के बाद हुई, दरगाह के बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा सैकड़ों जायरीन व खादिमों की मौजूदगी में अदा की गई। अब चांद दिखाई देने पर 21 या 22 दिसंबर से उर्स की विधिवत धार्मिक रस्मे शुरू होंगी। छह दिवसीय उर्स के दौरान जन्नती दरवाजा आम जायरीन के लिए खोला जाएगा।

खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि सदियों पहले संदेश देने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, उस समय झंडे चढ़ाकर संदेश दिया जाता था। उर्स में झंडा चढ़ाने की परंपरा अफगानिस्तान के बादशाह ने शुरू की थी, इसके बाद गौरी परिवार नियमित रूप से झंडे की रस्म निभाता चला आ रहा है। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार के फखरुद्दीन गौरी और सैयद मारूफ अहमद की सदारत में बुधवार शाम को असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना हुआ। जुलूस के आगे ढोल ताशे और कव्वाली गाते हुए शाही कव्वाल चल रहे थे, जुलूस में खादिम समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। जुलूस में बैंड-बाजे सूफियाना कलाम की मधुर धुन बजाते चले। जुलूस दरगाह के गेस्ट से शुरू हुआ, जो लंगर खाना गली, नला बाजार होता हुआ दरगाह के निजाम गेट में पहुंचा। झंडे को चूमने और छूने के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। तोपों की आवाज के साथ और शाहजहांनी गेट की छत पर शादियाने बजने के साथ बुलंद दरवाजे पहुंचने पर गौरी परिवार द्वारा परंपरा के अनुरूप झंडे को फहराया। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। तोपों की आवाज संग जुलूस आगे बढ़ा। शाहजहांनी गेट की छत पर शादियाने बजाए गए। झंडे की रस्म के साथ उर्स की औपचारिक शुरुआत हो गई। अब अकीदतमंद की आवक धीरे-धीरे बढ़ेगी। रजब का चांद दिखाई देने पर अब उर्स की विधिवत शुरुआत 21 या 22 दिसंबर से होगी। इसके साथ ही दरगाह में अकीदतमंद की संख्या बढ़ती चली जाएगी। उर्स के दौरान विभिन्न रसूमात और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

चयनित आरएएस निर्मल वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत

हत्या की आशंका को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने जाम लगाया।

बौंली-बामनवास, (निसं)। बरनाला तहसील के स्थित बैरखंडी गांव के निवासी नव चयनित आएएस अधिकारी निर्मल कुमार वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत को हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने बुधवार को भाड़ौती-मथुरा मेगा हाईवे पर स्थित बैरखंडी गेट पर 50 लाख रुपए मुआवजे एक स्थाई नौकरी एवं दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जाम लगा दिया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को आरएएस अधिकारी निर्मल कुमार वर्मा (25) एवं उनका साथी अमृत कुमार (16) निवासी बैरखंडी मलारना डूंगर अपने कार्यालय से अपने गांव की ओर जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आरएएस परीक्षा रैंक 1271 में चयनित की मौके पर ही मौत हो गई एवं साथी अमृत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मलारना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव एवं घायल को लेकर मलारना डूंगर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर घायल अमृतलाल को सवाई माधोपुर रैफर किया गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने बैरखंडी गेट मेगा हाईवे पर 50 लाख रुपए का मुआवजा एवं एक स्थाई नौकरी व सड़क दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जाम लगा दिया।

जाम की सूचना पर मलारना डूंगर एवं बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों व परिजनों से समझाइस की कोशिश की, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों ने एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना के बाद बामनवास एसडीएम प्रियंका कंडेला, मलारना डूंगर एसडीएम संतोष कुमार, बरनाला तहसीलदार भगवान सहाय मौके पर पहुंचे एवं कई दौर की समझाइस के बाद करीब 4:30 बजे ग्रामीण व परिजनों में वार्ता होने पर जाम खोल दिया एवं शव को मलारना डूंगर चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

कांग्रेसियों ने ईडी व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

दौसा (निस.)। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजीलाल ओड के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जिले भर के कांग्रेसियों ने ईडी व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साये कांठोसियोग ने केन्द्र सरकार का पुतला फूंका। उधर कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुये पुलिस

■ **केन्द्र सरकार का पुतला फूंका**

प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। प्रदर्शन से पूर्व कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला।

शहीद स्मारक कांठोसियो को सम्बोधित करते हुये जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावना पर लगातार प्रहार कर रही है। विपक्षी नेताओं को डराने, दबाने और जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई एवं विकास जैसे मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में झूठे व राजनीतिक द्वेष से प्रेरित केस बनाए गए हैं, जिन पर देश की सर्वोच्च अदालत में मामला विचाराधीन है और कांठोस को न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है।

पूर्व केबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। भाजपा सरकार ईडी जैसी एजेंसियों को अपना राजनीतिक हथियार बना चुकी है, लेकिन सच्चाई और लोकतंत्र की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांठोस पार्टी डरने वाली नहीं है और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष और तेज किया जाएगा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहती है, लेकिन कांठोस पार्टी ऐसी हर साजिश का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि कांठोस सड़क से लेकर सदन तक जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस दौरान पूर्व विधायक जीआर खटाना, पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज अवाना, नगर अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने भाजपा सरकार की कुनीति पर प्रहार किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला जिलाध्यध्यक्ष रेणु काटारिया, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा, चतरसिंह बासडा, प्रधान सुल्तान बैरवा, धन्ना लाल बैरवा, मंडल अध्यक्ष शरद नागर, दिलीपसिंह, लालसिंह राजपूत, रुक्मणी गुप्ता, जलजीत मीणा, रामहरि मीणा, महेश डोलिका, चंचल कसाना, उमाशंकर बनियाना, नरेंद्र जैमन, जगदीश श्यालावास, पीसी मीणा, कवरपाल गुर्जर, बलिराम सैनी, मंजू मीणा, किशनलाल कोली, कृष्ण जीरोता, प्रवक्ता मुकेश राणा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फिर आइपीएल तक पहुंचा भरतपुर का लाल

भरतपुर (निस)। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल में सिलेक्ट होने के बाद बुधवार को कार्तिक अपने पिता मनोज शर्मा और मां राधा शर्मा के साथ भरतपुर पहुंचे। यहां अठावाल भवन में कार्तिक और उनके मां-बाप को सम्मानित किया गया। भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हुए इस कार्यक्रम में शहर के लोग भी शामिल थे। कार्तिक का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। करोड़ों में बिकने वाले कार्तिक अपने संघर्ष के दिनों में रेन बसेरे तक में पिता के साथ सोए। कार्तिक के पिता मनोज शर्मा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि- क्रिकेट के लिए हम दोनों बाप-बेटों को भूखा रहकर रात गुजारी।कार्तिक के पिता ने बताया कि एक बार मैं ग्वालियर में एक टूर्नामेंट में कार्तिक के साथ गया था।

भूमि आवंटन की मांग तेज

दौसा (निस.)। विधानसभा क्षेत्र महवा के अंतर्गत नवगठित मनोहरपुर-खेडला पंचायत समिति के स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग अब तेज हो गई है। इस संबंध में पूर्व विधायक डॉ. ओमप्रकाश हुडला ने जिला कलेक्टर दौसा को सौंपकर पंचायत समिति भवन के लिए खेडला बुजुर्ग में भूमि आवंटित किये जाने की मांग की।

■ **पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने कलेक्टर को आम जन के साथ सौंपा ज्ञापन**

पूर्व विधायक डॉ. ओमप्रकाश हुडला ने पत्र में बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनोहरपुर-खेडला को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, किंतु अभी तक समिति का अपना स्थायी भवन नहीं होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में असुविधा उत्पन्न हो रही है। पंचायत समिति क्षेत्र की अनेक ठााम पंचायतों से जुडे विकास कार्यों, जनसमस्याओं के निस्तारण और प्रशासनिक बैठकों के लिए स्थायी भवन की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने पत्र में बताया कि खेडला बुजुर्ग स्थित शहीद मोहनसिंह स्मारक के पास उपलब्ध सरकारी भूमि को पंचायत समिति भवन के लिए आवंटित किया जाए। पत्र के अनुसार संबंधित भूमि खसरा संख्या 2103/2100 में स्थित है, जिसमें लगभग 25 बीघा भूमि उपलब्ध है, जो पंचायत समिति भवन एवं उससे संबंधित कार्यालयों के लिए उपयुक्त बताई गई है।

उन्होंने कहा कि जो भूमि वर्तमान महवा विधायक ने आबंटित करने की बात कहीं हैं वह पूर्ण रूप से मौजूद पंचायत समिति के नागरिकों के लिए उचित नहीं हैं जबकि खेडला बुजुर्ग में पर्याप्त मात्रा में चारागाह भूमि उपलब्ध हैं। और यहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि उक्त भूमि का शीघ्र आवंटन किया जाता है तो पंचायत समिति का भवन निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हो सकेगा, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रशासनिक सुविधाएँ उनके निकट ही उपलब्ध होंगी।

इससे ठाामीणों को दौसा या अन्य स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय व धन दोनों की बचत होगी। डॉ. हुडला ने जिला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया है कि इस विषय में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ठाामीणों ने भी पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटन की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पंचायत समिति बनने के बाद से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएँ बनी हैं, लेकिन स्थायी भवन के अभाव में कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे हैं। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है और विकास कार्यों को गति कब मिलती है।

जेल में जातिगत भेदभाव नही

फुलेरा। मॉडल जेल मैन्युअल 2016 के तहत गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स की ओर से फुलेरा उप कारागृह भवन का संयुक्त रूप से जेल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की अध्यक्षता अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति सांभर लेक (लिंक अधिकारी) डॉ. ऋचा कौशिक ने की। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध बंदीगणों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। बंदियों ने बताया कि जेल में किसी भी प्रकार का जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही कार्य व्यवस्था में भी सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। उप कारागृह के लंगरखाना (रसोई) में कार्यरत बंदियों से भी बातचीत की गई, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि भोजन व्यवस्था व कार्य विभाजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सांभरलेक ऋषिराज कपिल, व भागचंद कुमावत सहित उप कारापाल भरतलाल मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

जयपुर ग्रामीण सांसद कोष से खेलों के प्रोत्साहन के लिए राशि देने की घोषणा

जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के दिशानिर्देश में सांसद खेल महोत्सव 2025 का पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ।

शाहपुरा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के दिशानिर्देश में सांसद खेल महोत्सव 2025 का पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह, सुरेश कुमार बादलीवाल जिला अध्यक्ष जयपुर देहात उत्तर, आलोक बेनीवाल पूर्व विधायक शाहपुरा, यादराम जांगल संयोजक सांसद खेल महोत्सव, अजय सिंह रुडल सहसंयोजक सांसद खेल महोत्सव, भाजपा पूर्व जिला मंत्री एवं पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष व ठााम पंचायत खोरी जीएसएस अध्यक्ष एवं सांसद खेल महोत्सव शाहपुरा मंडल प्रभारी रवीश खटाणा, बंशीधर सैनी नगर परिषद सभापति शाहपुरा, पूर्व प्रधान एवं भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष मंजू सैनी शाहपुरा की गरिमामय उपस्थिति में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं झंडारोहन व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विद्यालय के खेल मैदान में कबड्डी, वालीबाल, दौड़ 100 मीटर व 200 मीटर का भव्य शुभारंभ हुआ।

भाजपा जयपुर जिला देहात उत्तर मीडिया प्रभारी सुभाष जोशी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पुरुष एवं महिला की कुल 299 टीम में 4936 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

इस दौरान शाहपुरा शहर मंडल, शाहपुरा देहात मंडल, मनोहरपुर मंडल में पुरुष एवं महिला की कुल 159 टीम में 2725 खिलाड़ियों जिसमे कबड्डी की कुल 105 टीम 975 खिलाड़ी, वॉलीबॉल की कुल 54 टीम 550 खिलाड़ी, दौड़ में कुल 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के ठाामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने एवं उनको आगे बढ़ाने के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिससे देश की युवा पीढ़ी शारीरिक, मानसिक रूप से सशक्त बन सके। इस दौरान उन्होंने जयपुर ठाामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह द्वारा सांसद कोष से खेलो के प्रोत्साहन के लिए राशि देने की घोषणा को भी दोहराया जिस पर उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह एवं पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की।

इस अवसर पर आलोक बेनीवाल टीम तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की टीम के बीच कबड्डी का उद्घाटन मैच हुआ जिसमें आलोक बेनीवाल टीम 12 - 5 से विजय हुई।

इस अवसर पर शाहपुरा उपखण्ड अधिकारी संजीव कुमार खेदर, पवन कुमार जाट सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम शाहपुरा, प्रधानाचार्य रुडमल कपूरिया शहरी नोडल अधिकारी शाहपुरा, प्रधानाचार्य संजय कुमार शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा, शाहपुरा नगर मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद मालीराम सैनी, मनोहरपुर मंडल अध्यक्ष रामचंद्र यादव, शारीरिक शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित सैकड़ो भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण

सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं पर टोंक में कई कार्यक्रम हुए।

टोंक। राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। विकास रथों में स्थापित एलईडी के माध्यम से आमजन को केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से रूबरू किया जा रहा है।

■ **विकास रथ का अवलोकन, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया**

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बुधवार को ग्राम पंचायत समिति टोंक की ग्राम पंचायत घास में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण किया।

उपखंड अधिकारी टोंक हकुमीचंद रोहलानिया एवं तहसीलदार भगवती लाल जैन से शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को आवासीय पट्टे, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित किया। साथ ही विकास रथ में ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाई जा रही सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास रथों के माध्यम से वीडियो व ऑडियो संदेशों तथा जनसंवाद के जरिए आम लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100407 **लोक सूचना** दिनांक: 17.12.2025

श्री RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI, पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी RIYASAT TOWER, KHASRA NO. 688/1, RAMPURA ROAD, BEHIND ISKON TEMPLE, SUKHIYA, S.F.S. MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302020 श्री SUGNA DEVI THROUGH POWER OF ATTORNEY BUDDHI PRAKASH CHOUDHARY पुत्र श्री MADAN LAL CHOUDHARY जाति JAT निवासी BADA PADAMPURA, SHIVDASPURA, CHAKSU, JAIPUR, RAJASTHAN - 303903 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	भाटेड, सांगानेर (जयपुर)	1.) सुगनादेवी पत्नि रामजीलाल हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा मुहाना खातेदार	1660/1062	0.15	0.15
2	बासडीजोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा पूर्ण जाति N/A पंजीकृत कार्यालय 709 ओके प्लस टॉवर सेक्टर 7 मानसरोवर जयपुर खातेदार	1377/1176	0.134	0.134
3			1378/1176	0.0867	0.0867
4			1388/1302	0.5889	0.5889
5	बासडीजोगियान, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नही मकान संख्या 0 कॉलोनी रियासत टावर खसरा नंबर/ क्षेत्र/स्थान रामपुरा रोड इस्कॉन मंदिर के पीछे सुखिया एस एफ एस मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	1386/1302	0.2375	0.2375
6			1385/1302	0.29	0.29
			कुल		1.4871

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करावें। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-12-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

हम कि केशर सिंह पुत्र श्री कारे सिंह, वैजन्ती पत्नी श्री केशर सिंह निवासीयान ग्राम कौंर, तहसील व जिला डीग (राज०) हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि हमारा एक पुत्र भूपेन्द्र सिंह आयु 30 वर्ष जो कि गलत सोहबत में पड़ गया है जो कि आये दिन हम पति-पत्नी के साथ झगड़ा करता है तथा हमें हमारे बनाये हुये घर में नहीं रहने देता है। भूपेन्द्र सिंह का चाल-चलन खराब होने के कारण ना तो हमारी बातें मानता है और हमारे द्वारा कमाये हुये पैसों को भी छिना लेता है हम भूपेन्द्र सिंह के द्वारा किये गये कृत्यों से बुरी तरह से आहत, तंग व परेशान हैं। इसलिये हम दोनों पति-पत्नी भूपेन्द्र सिंह को अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति में बेदखली करते हैं। अगर भविष्य में मेरा पुत्र भूपेन्द्र सिंह किसी दीगर व्यक्ति से उधारी व लेन देन करता है या कोई आपराधिक कार्य एवं अन्य धोखाधड़ी जैसे कार्य करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी भूपेन्द्र सिंह की होगी हम पति पत्नी का भूपेन्द्र सिंह से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा। इसके द्वारा किये गये कार्यकलाप लेन-देन की जिम्मेदारी भूपेन्द्र सिंह व इससे समव्यवहार करने वाले व्यक्ति ही जिम्मेदार होंगे। भूपेन्द्र सिंह का अब हमारी चल अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होगा।

नाम परिवर्तन

मैं GS191822X RANK OEM-1 जीतराम मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीना आयु 47 वर्ष जाति मीना नि. ग्राम रूंधपुरा तह. मासलपुर जिला करौली राज. का हूं यह कि मेरा पुत्र पंकज कुमार जिसकी जन्म तिथि 05.08.2010 है जो सही है। यह नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड में दर्ज है। मेरे पुत्र के कक्षा 8 व 10 की अंक तालिका में नाम व जन्म तिथि सही अंकित हो रही है। यह कि मेरे मेरे GREF सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार मीना तथा जन्म तिथि 05.06.2008 दर्ज हो रहे है जो कि गलत दर्ज हो गये हैं इसलिए मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार तथा जन्म तिथि 05.08.2010 दर्ज की जावें। यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पंकज कुमार तथा जन्म तिथि 05.08.2010 दुरूस्त किये जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-9007 दिनांक-09/12/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 32/473 (MIG-A), (एरिया 116.250 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन कुमारी विभा मुदगल (श्रीमती विभा शर्मा) पुत्री श्री प्रभुनारायण मुदगल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1954 दिनांक 28.12.1991 को जारी किया गया। कुमारी विभा मुदगल (श्रीमती विभा शर्मा) के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.03.2007 को उप पंजीयक जयपुर-प्रथम, के यहां पंजीकृत करवाये गये। कुमारी विभा मुदगल उर्फ श्रीमती विभा शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 04.10.2019 के द्वारा 1. श्रीमती सपां देवी पत्नी श्री मोटयो मल कुन्दनानी एवं 2. श्रीमती रेखा कुन्दनानी पत्नी श्री आसनदास कुन्दनानी को विक्रय कर उप पंजीयक-अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सपां देवी की मृत्यु दिनांक 09.01.2023 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री सांवल दास कुंदनानी पुत्र स्व. श्री मोटयो मल द्वारा उक्त आवास 1/2 हिस्से को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 1. श्री सांवल दास कुंदनानी पुत्र स्व. श्री मोटयो मल एवं 2. श्रीमती रेखा कुन्दनानी पत्नी श्री आसनदास कुन्दनानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 101/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री राजीव शर्मा प्रन्यासी ने पंजीकृत मंदिर श्री मुरली मनोहर जी प्रोस मुण्डोला ग्राम-मुण्डोता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 2 जयपुर 1999 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास में श्री पुरुषोत्तम शर्मा अध्यक्ष एवं श्री वैध बिरधीचन्द शर्मा सचिव का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने उनके स्थान पर स्वयं का नाम बतौर प्रन्यासी/अध्यक्ष, व सतीश शर्मा को सचिव/प्रन्यासी तथा कैलाश चन्द शर्मा को कोषाध्यक्ष, बालकृष्ण शर्मा, श्री संजय शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा व श्री यशु शर्मा नियुक्त कर उनके नाम प्रस्यात रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 15/12/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 19/1/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 102/2025

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री भगवान राम लक्ष्मीनारायण जागिंड ने पंजीकृत प्रन्यास भगवान राम लक्ष्मीनारायण जागिङ सिगोवडी ट्रस्ट 316, क्रास रोड माल, सैन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 108 जयपुर 2018 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास का कार्यालय का पत्ता पलैट में 621. शिवशक्ति पैराडाईज, सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर जयपुर कर तथा शाखा कार्यालय ठााम सिंगोदडी पोस्ट सिंगोदडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थापित कर उक्त संशोधनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है. में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निश्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

15/12/25 आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 19/1/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी न. JC 453412W Sub Ajay Singh यूनिट 24 गार्ड (17 ग्रेनेडियर्स) मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार सिंह (Suresh kumar Singh) और जन्मतिथि 01.07.1958 जो की गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम सुरेश सिंह (Suresh SINGH) है। और उनकी जन्मतिथि 01.01.1964 है

मैं आर्मी न. JC 453412W Sub Ajay Singh यूनिट 24 गार्ड है। (17 ग्रेनेडियर्स) मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे माता जी का नाम आशा देवी (Asha devi) है और जन्म तिथि 01.07.1960 है जो की गलत है। मेरे माताजी का सही नाम आशा सिंह (Asha SINGH) है। जिनकी सही जन्मतिथी 01.01.1958 है।

I hitherto known as SHIVHAREE GURJAR, S/o KARANSINGH GURJAR, R/o Village Karanpur, Post Patoli, Tehsil, Mahwa, DIST: Dausa, Rajasthan-321608, have changed my name and shall hereafter be known as GURJAR UDAL BANESINGH.

I hitherto known as DIMPY, W/o KIROD CHAND, R/O Guwalda, PO: Gwalda, DIST: Alwar, Rajasthan-301707, have changed my name and shall hereafter be known as HEMLATA.

लोक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100405 दिनांक: 17.12.2025

श्री DREAM LAND DEVELOPERS पुत्र श्री DIRECTOR AMIT JAIN जाति JAIN निवासी 21/5-B MADHYAM MARG MANSAROVAR JAIPUR RAJ. श्री AMIT JAIN पुत्र श्री JINENDRA KUMAR JAIN जाति JAIN निवासी 76 2 ND FLOOR LAXMAN COLONY NEW SANGANER ROAD WARD NO 30 SODALA JAIPUR RAJ. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
लखेर, आमेर (जयपुर)	अमित जैन डायरेक्टर ड्रीम लैंड डवलपर्स पुत्र जिनेन्द्र कुमार जैन	317	3.62	3.62
		317/1335	2.1	2.1
	अमित जैन डायरेक्टर ड्रीम लैंड डवलपर्स	317/1346	0.06	0.06
		304	1.4	1.4
	हिस्सा 2/5	317/1345	0.03	0.03
	ड्रीम लैंड डवलपर्स	304/1337	0.63	0.63
	हिस्सा 3/5	304/1344	0.06	0.06
	ड्रीम लैंड डवलपर्स	317/1311	3.61	3.61
		317/1444	0.04	0.04
		317/1348	0.1	0.1
		317/1445	2.05	2.05
			कुल	13.7

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करावें। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.12.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 45/184, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर के RHB द्वारा जारी मूल अलोटमेंट लेटर, पजेशन लैटर, कैश जमा रसीद कहीं खो गये है कृपया मिलने पर सूचित करें। भीम सिंह केशवानी, 7791991049

मेरा मकान सं. 32/406 (C) SEC-3, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल भौतिक कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- SMT. NIDHI JAIN- 6376203310

यह की मेरे निजी खातेदारी योजना सिल्वर सिटी में 1-57, 1-58 के मूल दस्तावेज गुम हो गए है। साइट प्लान रसीद आवंटन-पत्र मिलने पर सूचित करें। संदीप जोशी, मो.9811999922

The original documents for my house, number 183/01, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, including the Seven Days letter and the possession certificate (Certificate for Handing Over the House/ Declaration), have been lost. Please inform me if found. Kaushal Kumar Gautam– 9828084139

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला - अजमेर (राज)

क्रमांक/नपकि/विकास/2025/2482 दिनांक – 12.12.2025

निविदा सूचना संख्या – 29/2025–2026

नगर परिषद किशनगढ द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना अनुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदको /ठेकेदारो से मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.12.2025 को 12.00 बजे तक निविदा शुल्क मय धरोहर नकद राशि जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 23.12.2025 को मध्यान्ह पश्चात् 02.00 P.M. तक प्राप्त की जाकर उसी दिन उपस्थित संवेदकों के समक्ष 03.00 **P.M.** पर खोली जावेगी। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार परिषद को होगा। निविदाएं बेचने/प्राप्त करने के दिवस को किसी भी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होने पर कार्यवाही आगामी कार्य दिवस को सम्पादित की जावेगी। निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://sppp.rajasthan.gov.in/** पर देखी जा सकती है।

यूबीएन नं.–DLB2526A9126

आयुक्त
नगर परिषद्, किशनगढ़

राज.संवाद/सी/25/15994

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जयपुर)

E-mail :- eesanganerzone01@gmail.com

क्रमांक :– जसअ/2025/361 दिनांक: 15.12.2025

निविदा सूचना संख्या 193–197/2025–26

केन्द्र एवंराज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेद कों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि. अभि. (सांगानेर जोन) से संबंधित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://sppp.raj.nic.in** & **www.jaipurmc.org** पर देखी जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टलका **Unique Bid Number JMC2526WSOB02237** से **JMC2526WSOB02241** है।

अधिशाषी अभियंता
सांगानेर जोन
नगर निगम जयपुर

राज.संवाद/सी/25/15951

IARC इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

कॉपोरेट कार्यालय-ए-601, 6वीं मंजिल, 215 एट्रियम अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबल 400083 पंजीकृत कार्यालय-406, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017

सीआईएन नंबर-U74999012002PIC117525

ईमेल-iarc@iarc.co.in, वेबसाइट-www.iarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट- IV ए) (नियम 8(6)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित

आम जनता को और खास तौर पर, नीचे बताए गए बॉरोअर, गारंटर और मॉर्टगेजर को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताया गया सिक्योर्ड एसेट जो इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास मॉर्टगेज है जो RetCo-5 (जिसे आगे "IARC" कहा जाएगा) के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है, जिसका कॉपोरेट ऑफिस A-601/602/605, 6th फ्लोर, 215 एट्रियम, कनकिया स्पेसेस, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400093 में है, और जिसका पजेशन IARC के ऑथराइज्ड ऑफिसर (AO) ने ले लिया है, उसे IARC के ड्यूज की वसूली के लिए "AS IS WHERE IS", और "WITHOUT RECORSE" बेसिस पर बेचा जाएगा। यह सेल नीचे साइन करने वाले द्वारा वेबसाइट www.iarc.co.in पर उपलब्ध ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के जरिए की जाएगी।

कर्जदारः कर्जदार श्री विकास कुमार **सह-उधारकर्ता श्रीमती शिवानी शर्मा**

डिमांड नोटिस तारीख और रकम **तारीख 16.09.2024**

राशिः रु.15,67,939/- (केवल पंद्रह लाख सड़सठ हजार नौ सौ उनतीस रुपये) बोली बढ़ाने की रकमः 10,000/- (सिर्फ़ दस हज़ार रुपये)

अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरणः यूनिट नंबर टी-1, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर एच-160 पर निर्मित, मंगलम सिटी, ब्लॉक-एच खुशी रेजीडेंसी, गांव पीथावास, निवारू, कलवार रोड, तहसील और जिला जयपुर, राजस्थान, 302012

एरिया नापः कारपेट एरिया, 758 sq.ft. सुपर बिल्ट-अप-एरिया 1109.60 sq.ft. घिरा हुआः उत्तरः प्लॉट नंबर H-159, दक्षिणः प्लॉट नंबर H-161, पूर्वः प्लॉट नंबर H-171 पश्चिमः रोड

प्रतीकात्मक कब्जे की तारीख	01.12.2025 तक कुल बकाया	आरक्षित मूल्य	(EMD) बयाना राशि जमा
03.12.2025	रू.12,51,801.76 (रूपये बारह लाख इक्यावन हजार आठ सौ एक पैसे छिहत्तर मात्र)	रू.15,53,440/- (केवल पंद्रह लाख तिरपन हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र	रू. 1,55,344/- (केवल एक लाख पचपन हजार तीन सौ चौवालीस रूपये)

प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन की तारीख-09.01.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक) EMD की आखिरी तारीख 19.01.2026 ई-ऑक्शन की तारीख/समय 20.01.2026/सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वे ज्यादा जानकारी क्लेरिफिकेशन या अपनी एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेल के डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कृपया IARC की वेबसाइट www.iarc.co.in पर मौजूद लिंग देखें। जो लोग इंटरेस्टेड है वे किसी भी मदद के लिए मिस्टर गुलशन से +91-9211309232 पर या मिस्टर कौशल से +91-9211309957 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते है।

जगह-मुंबई, तारीख 17.12.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा) राज.

Mail ldnpkishangarhbas@gmail.com, PH.01460-242233

क्रमांक-न.पा.कि.बास/2025/4070 दिनांकः 16/12/2025

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 69-क के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रार्थी ऑनलाईन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 03 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
1	हेमनदास	थावर दास	वार्ड नं. 09 रैणी मौहल्ला कि.बास	535
2	गिरधारी सिंह	कंवर सिंह	वार्ड नं. 08 किले के पास कि. बास	535
3	रिछपाल सिंह	श्रीचन्द	वार्ड नं. 20 बासड़ा कि. बास	689
4	भूवनेश गोपाल कमल	सुरेश चंद	वार्ड नं. 09 रैणी मौहल्ला कि. बास	535
5	रामजीत	श्रीचंद	वार्ड नं. 02 बासकृपाल नगर कि. बास	424
6	सरजीत	श्री चंद	वार्ड नं. 02 बासकृपाल नगर कि.बास	424
7	रणजीत	श्रीचंद	वार्ड नं. 02 बासकृपाल नगर कि.बास	424
8	योगेश कुमार	घीसाराम	वार्ड नं. 09 खुराना चौक के पास कि.बास	535

उपरोक्त व्यक्ति को 69-क एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 03 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका किशनगढ़बास

संक्षिप्त

शिविर 19 से शिविर

दौसा (निस.)। जिले में सुशासन सप्ताह के तहत 19 से 25 दिसम्बर तक 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान चलाया जाएगा। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन की धारणा को बल देने के उद्देश्य से संचालित हो रहे इस अभियान के अन्तर्गत ठाामीण समस्या समाधान शिविरों के साथ लोक शिकायतों के निस्तारण एवं उन्नत सेवा प्रदायगी के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के अलावा 23 दिसम्बर को सुशासन संबंधित नवाचारों पर चर्चा के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन मे उनियारा थानाधिकारी द्वारा गठित टीम ने चोरी व अन्य प्रकरणो में कार्यवाही करते हुए उनियारा थाना क्षैत्र में चोरी के आरोपी राजेश पुत्र जगदीश जाट उम्र 26 साल निवासी खेलनिया थाना उनियारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इसी क्रम में उनियारा थाना पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट पर कार्यवाही करते हुए एक वर्ष से फरार स्थाई वारंटी राकेश पुत्र सुवालाल जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी बैरवा की ढाणी उटीटाणा थाना सदर टोंक को गिरफ्तार किया गया है।

सैशन न्यायाधीश का स्वागत

कोटपूतली । नवपदस्थापित जिला एवं सैशन न्यायाधीश रवि शर्मा के पदभार ठाहण करने पर अभिभाषक संघ कोटपूतली एवं पावटा द्वारा माला व साफा पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एडीजे प्रथम डॉ. राजेश कुमार, एडीजे चतुर्थ डॉ. सुरेश कुमार, सीजेएम डिम्पल जंडैल, एसीजेएम सिमरन कौर व डॉ. अजय कुमार बिश्नोई, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा धानिया का भी स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड. बजरंग लाल शर्मा, सचिव मुकेश यादव का सम्मान भी किया गया।

दौसा में ट्रॉमा एवं आपातकालीन के नवीन भवन का उद्घाटन

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में ट्रोमा एवं आपातकालीन के नवीन भवन का उद्घाटन किया।

■ आधुनिक यूनिट क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी : डॉ. किरोडीलाल मीणा

दौसा (निस.)। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को समय पर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

डॉ. किरोडीलाल मीणा बुधवार को श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा एवं आपातकालीन के नवीन भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे। उन्होने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को समय पर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सेवाएं जीवन रक्षक होती हैं और इस नए भवन के शुरू होने से दौसा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ग्रामीण व जिला स्तर पर भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक यूनिट क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ओपीडी समय के बाद भी इस यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक ऑन-कॉल उपलब्ध रहेंगे, जिससे दुर्घटना या आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल और बेहतर उपचार मिल सकेगा।

डूंगरी बाध के विरोध को लेकर झलका दर्द : समारोह को सम्बोधित करते हुये कहा कि डूंगरी बांध को लेकर कुछ लोगो को द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि मेरे आग्रह पर पर डूंगरी बांध की ऊंचाई को 3 मीटर कर किया गया है, जिसके कारण अब मात्र 9 गांव ही प्रभावित होगें, जबकि अफवाह फैलाई जा रही है कि 78 गांव प्रभावित हो रहे है जिसके कारण डूंगरी बांध का विरोध कर रहे है। उन्होने कहा कि डूंगरी बांध की ऊंचाई 3 मीटर कम नही की जाती तो संभवत:35 गांव प्रभावित होते, ऊंचाई कम करने से 9 गांव को ही विस्थापित किये जावेगें। डूंगरी बांध के निर्माण से औद्योगिक ईकाइयां खुलेगी, 15 प्रतिशत पानी उद्योगो को दिया जावेगा। उन्होने कहा कि ये देश ही ऐसी पहली परियोजना है जिसमें प्रभावित लोगो को उनके इच्छित स्थान पर जमीन की दी जावेगी साथ ही सरकार द्वारा उन्हे मकान बनाकर दिया जावेगा। इससे पूर्व ऐसी कई परियोजनाएं आई, जिसमें केवल जमीन की राशि दी जाती थी। उन्होने कहा कि ईआरसीपी परियोजना को लेकर मैने खुब आन्दोलन किया, जब हम सत्ता में आये तो लोग कहने लग गये कि डॉ. किरोडीलाल मीणा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ जेल में रहे है दोनो दोस्त है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यो नही दिलाते है, आज वही लोग डूंगरी बांध का विरोध कर रहे है। डूंगरी बांध बीसलपुर से भी बडा बांध होगा, इसकी क्षमता अधिक रहेगी। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा सहित आसपास के जिलो को इसका लाभ मिलेगा। कोरिडोर बनेगा, बडे बडे उद्योग लगेगें, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा कि हमारा उद्देश्य दौसा की जनता को ईसरदा से जल उपलब्ध कराना है, अगली गर्मी तक पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला, सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीणा, पूर्व सभापति राजकुमार जायसवाल, धुंधीराम धडंगा, जिला महामंत्री विपिन जैन, जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत, सिकंदर वादावन, नर्सिंग ट्यूटर धर्मपाल मीणा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अन्य पिछडा वर्ग आयोग की जनसुनवाई 22 को

दौसा (निस.)। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में जिला परिषद सभागार में 22 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक जनसुनवाई करेगा।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि पांच सदस्यीय समर्पित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ठाामीण व शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं उसके निहितार्थों की समसामयिक एवं अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच व अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को निश्चित समय में प्रस्तुत करनी है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुभवजन्य तरीके से अध्ययन करने के क्रम में आयोग जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर इस विषय में जनसुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं गोपाल कृष्ण शर्मा दौसा में जनसुनवाई करेंगे।

जनसुनवाई में आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विचार जानने के लिए उनसे चर्चा की जाएगी और अभ्यावेदन लिए जाएंगे। जनसुनवाई के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चन्द गंगवाल को नोडल अधिकारी एवं नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीना को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

रक्तदान शिविर आयोजित

कोटपूतली । केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आगामी 19 दिसम्बर शुक्रवार को प्रात: 10 बजे राजमार्ग स्थित मोरीजावाला धर्मशाला में विषाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा।

शिविर में जीवनदाता ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संठाहण किया जायेगा। कार्यक्रम संयोजक भाजपा एस. सी. मोर्चा के प्रदेश मंत्री एड. सुबेसिंह मोरोडिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल होगें। जबकि अध्यक्षता श्री गुरु रविदास विष्व महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री रवि शेखर मेघवाल द्वारा की जायेगी। वहीं विषिष्ठ अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिष्नोई, एडीएम ओमप्रकाश सहारण, भाजपा नेता बनवारी लाल यादव व कर्मवीर बोकन, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड. बजरंग लाल शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुगन चन्द्र आर्य, शिक्षाविद् डॉ. आर. के सिंह आदि भाग लेगें।

'वरिष्ठजनों की सेवा मेरी पहली प्राथमिकता'

दौसा । दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि वैसे तो दोसा क्षेत्र की जनता के हर व्यक्ति के लिए ही मेरे दरवाजे सदैव सेवा के लिए खुले हुए हैं उसके बावजूद भी यदि मेरे आवास पर या मेरे संपर्क में कोई भी वरिष्ठ जन अपना काम लेकर आते है तो मैं वरिष्ठ जनों को प्राथमिकता देता हूं और देता रहूंगा। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा बुधवार को पेंशनर दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे। उन्होने कहा कि पेंशनर समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट कम होने पर भी पेंशनर भवन की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपये की स्वीकृत कर चुका हूं तथा जरूरत के अनुसार और भी सेवा करता रहूंगा। समारोह में उपस्थित विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पेंशनरों ने गीत संगीत एवं काव्य पाठ के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इन्हें देखकर विधायक ने वरिष्ठ जनों के जोश एवं रचनात्मकता की तारीफ की और कहा कि पेंशनर घर परिवार के साथ समाज का भी मार्गदर्शन एवं सेवा करते रहे। पेंशनर समाज के वरिष्ठ संवाहक सीताराम शास्त्री ने राज्य स्तरीय पेंशनर संगठन के प्रवर्तक डी एस नकारा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वही शीतल चौबे, भगवान वर्मा आदि ने भी विचार रखें। सहायक जिला कोषाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने जिला कोष कार्यालय संबंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए सदा सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में महेश राजपुरोहित, नाथूलाल शर्मा, आर्टिस्ट कजोड़ मल, मोहनलाल छारड़ा, मुकुट बिहारी पाठक, कैलाश गहलोत, रमेश चंद्र, महासंघ अध्यक्ष एनआर बालोत, शंभू दयाल गुप्ता, अशोक कुमार शर्मा, केदार प्रसाद जोशी, कालूराम सैनी, कवि कृष्ण राज सैनी, ओम प्रकाश मिमिक्री, राधेश्याम बालाहेडी, नरेंद्र शर्मा कोष कार्यालय तथा शकीन खान सहित बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन पेंशनर मौजूद रहे।

सार-समाचार

मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भरतपुर (निस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर पीसीसी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर मोदीशाही सरकार का जिले के समस्त जिला, ब्लॉक, महिला कांग्रेस, सेवादल, यूथ कांठोस, एनएसयूआई सहित तमाम प्रकोष्ठों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बिजली घर चौराहे पर पुतला फूंका गया।जिला संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा ईडी,सीबीआई एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने एवं इन संस्थानों पर दबाव डालकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड मामले में कराई गई झूठी एफआईआर को न्यायालय द्वारा निरस्त करने एवं मोदी सरकार को फटकार लगाने के संबंध में मोदी शाही सरकार का पुतला दहन भरतपुर जिला मुख्यालय पर किया गया। पुतला दहन से पहले वक्ताओं ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा भाजपा सरकार द्वारा कराई गई झूठी एफआईआर को निरस्त करने एवं सरकार को फटकार लगाने से साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपने पद एवं सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं एवं देश में संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार करके देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कांठोस पार्टी सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने का एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का बचाने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने किया। कार्यक्रम में साहब सिंह चौधरी, श्रीभगवान कटारा ,मनोज पटेल, रामेश्वर सैनी, बबीता शर्मा,निरंजन जघीना, चंद्रभान फौजदार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

गांवों में पहुंची विकास रथ यात्रा

कोटपूतली । वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन व जनकल्याण के संकल्प के साथ कोटपूतली विधानसभा के उत्तर मंडल में निकाली गई विकास रथ यात्रा बुधवार को ग्राम पंचायत देवता, बनार, बनेठी, बखराना, रायकरणपुरा पहुँची। इस दौरान ग्रामीण समस्या समाधान शिविर प्रभारी तहसीलदार रामधन गुर्जर ने बनेठी में आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा किये गये ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कार्यों की जानकारी साझा की। राज्य सरकार हर गाँव, गरीब व वर्ग के उत्थान हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष एड. रमेश रावत, विकास रथ यात्रा के कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र सिंह तवर, मंडल उपाध्यक्ष विजय सिंह, कैलाश जांगिड़, सुरेश यादव, पंसस प्रतिनिधि मनोज कुमावत समेत कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आरोपी गिरफ्तार

टोंक। निवाई में ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी, हादसे में कॉन्स्टेबल व सरकारी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कांस्टेबल को हल्की चोट आई। बाद में निवाई सदर पुलिस ने कार्यवाही करते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दत्तवास थानधिकारी ने बताया कि आरोपी हेमराज गुर्जर पुत्र प्रहलाद गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी रामचन्द्रपुरा थाना दत्तवास के खिलाफ सार्वजनिक सम्पती नुकसान निवारण अधिनियम के तहत थाना दत्तावास में मामला दर्ज कर घटना में प्रयुक्त ट्रेक्टर को जप्त किया गया है। आरोपी पहले से ही वांछित चल रहा था।

जलदाय मंत्री का आभार जताया

कोटपूतली । राज्य सरकार द्वारा विधायक हंसराज पटेल की अनुशंषा पर कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरूण्ड में 40.67 लाख की लागत से 02 थ्री फेज बोरिंग एवं पाईपलाईन कार्य स्वीकृत किया गया हैं। उक्त स्वीकृति पर विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जल संकट के समाधान की दिशा में यह एक मजबूत पहल हैं। इससे ग्रामीणों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा, यह एक अत्यंत सराहनीय एवं जनहितकारी निर्णय है। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा और वर्षों से चली आ रही जल समस्या से राहत मिलेगी।

फुलेरा में अतिक्रमण हटाने व पॉलीथिन पर सख्ती तय

फुलेरा शहर की सुंदरता व व्यवस्था को लेकर पालिका-व्यापार महासंघ की अहम बैठक हुई।

फुलेरा। फुलेरा में शहर की सुंदरता बनाए रखने एवं बाजार व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बुधवार को नगरपालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार शर्मा की पहल पर व्यापार महासंघ को आमंत्रित कर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी ने फुलेरा की सुव्यवस्थित बसावट की सराहना करते हुए कहा कि अस्थायी अतिक्रमण व अव्यवस्थित ठेला व्यवसाय के कारण शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है। बैठक में गणगौरी बाजार, हलवाई बाजार, इंदिरा मार्केट एवं शहर के प्रमुख गांधी चौक को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि गांधी चौक में ठेला व्यवसायियों को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाएगा। गणगौरी बाजार को नॉन-वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा, जबकि हलवाई बाजार व इंदिरा मार्केट में सड़कों पर खड़े ठेले हटाकर उन्हें तथा गणगौरी बाजार के ठेला व्यवसायियों को ज्योतिबा फुले सर्किल पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही गांधी चौक से सब्जी मंडी तक संकरे हो चुके मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए नगरपालिका द्वारा आगामी तीन दिनों तक सब्जी मंडी के व्यापारियों व ठाहकों को पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी जाएगी, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यापार महासंघ द्वारा सभी व्यापारियों से दुकानों पर डस्टबिन रखने तथा कचरा पालिका की कचरा संठाहण गाड़ी में ही डालने की अपील की जाएगी। गणगौरी बाजार में स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यस्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की आवश्यकता भी बताई गई।

विकास कार्यों की जानकारी ली

भरतपुर (निस)। राज्य सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में आयोजित किए जा रहे विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी के दूसरे दिन बुधवार को उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला।

बढसंख्या में आमजन के साथ विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर मिलेनियम स्कूल के लगभग 120 विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। विद्यालय के कक्षा आठवीं के उमंग, गंगन गुर्जर, पृथ्वी, मुकेश सहित अन्य विद्यार्थियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का गहनता से अवलोकन किया।

विद्यार्थियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उत्सुकता के साथ प्राप्त की।

विराटनगर, पावटा में सांसद खेल महोत्सव शुरू

■ नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खेल प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरक- देवायुष

पावटा। बुधवार को युवाओं में खेल भावना, स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराटनगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन किया गया। विराटनगर में कार्यक्रम का शुभारंभ विराटनगर विधान सभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड ने दीप प्रज्वलन कर व झंडारोहण कर किया और उपस्थित खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक धनकड ने कहा कि फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सांसद खेल महोत्सव उसी दिशा में एक सशक्त पहल है, जिससे ठाामीण और शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकें। उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। खेल शपथ के माध्यम से खिलाड़ियों ने खेल को खेल भावना से खेलने, अनुशासन बनाए रखने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। वही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ जयपुर ग्रामीण सांसद प्रतिनिधि देवायुष सिंह ने दीप प्रज्वलन कर व झंडारोहण कर किया और उपस्थित खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई। सांसद प्रतिनिधि देवायुष सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शारीरिक और मानसिक विकास को हमेशा प्राथमिकता दी गई है, जिसका उल्लेख प्राचीन ठांथों और वेदों में भी मिलता है। धनकड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया पहल की सराहना की, इसे युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खेल प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा कर राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ी देश-विदेश में तिरंगा फहराकर भारत की पहचान को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों को करियर के रूप में अपनाने तथा अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का अ किया। कार्यक्रम में विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय, सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

भरतपुर में भाजपा महिला सम्मेलन को लेकर बैठक

■ ऐतिहासिक जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए धौलपुर में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन होगा

भरतपुर (निस)। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय भरतपुर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में आयोजित की गई। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए धौलपुर में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक में रूपरेखा तैयार की गई। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सेवा पखवाडा लोकसभा प्रभारी हमीद खान मेवाती ने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख किया। जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने धौलपुर महिला सम्मेलन में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर जोर दिया। जिला मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेन्द्र पचौरी ने बताया कि 19 दिसम्बर को धौलपुर में संभाग स्तरीय महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्बोधित करेंगे। बैठक में नव गठित जिला कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्र जैन, जिला उपाध्यक्ष बृजेश अग्रवाल, श्याम सुन्दर गौड, रज्जन सिंह, जगदीश अजान, सतीश बंसल, मनीश शर्मा, प्रवेश धर्मसिंह चौधरी, गौरव सरपंच, लाखन पहलवान, जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा, गोविन्द चौधरी, जगत गुर्जर, जिला मंत्री महावीर डागुर सुन्दर सिंह, बबली नवीन दुबे, नरेन्द्र सिंघल, अली हुसैन, जगमोहन खटाना, मुन्नी लक्ष्मण ठाकुर, रामदयाला धाकड, फूलवती नेताराम जाटव, कोशाध्यक्ष हेमन्त अग्रवाल, मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेन्द्र पचौरी, कार्यालय प्रभारी उत्तम षर्मा, जिला प्रवक्ता दिनेश लवानियां, अनुराग तमरौली, कुलदीप पोसवाल, राहुल चौधरी, देवेन्द्र चामड, भावना गांधी, शेरसिंह धरसौनी, मंजीत गुलाटी, दीपेन्द्र गनेशिया, गिरीश भारद्वाज, संतोश खण्डेलवाल, अनिल गोयल, कृश्णा जाट, आशीश खण्डेलवाल, नरेन्द्र शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष रमन धाकड, महिला मोर्चा जिला संयोजक कविता गोयल, मण्डल अध्यक्ष चन्द्रवीर ब्रिजेन्द्र सिकरोंदा, मानसिंह, प्रह्लाद सिह, महेश यादव आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अनदेखी पड़ी महंगी

भरतपुर (निस)। केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' में निवर्तमान सांसद (भरतपुर) रंजीता कोली को सूचना न दिए जाने का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर हो गया है। बैंक प्रशासन और राज्य सरकार के बीच समन्वय न बैठने के कारण कार्यक्रम में उनकी अनदेखी की गई। इस संबंध में रंजीता कोली द्वारा 21 नवंबर को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, अरुण प्रकाश शर्मा ने जिला कलेक्टर, भरतपुर कमर चौधरी को आदेश जारी किए हैं कि वे पूरे मामले की तत्काल जांच कर तथ्यात्मक टिप्पणी सहित रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करें। जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम भरतपुर के वीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें न तो निवर्तमान सांसद रंजीता कोली को आमंत्रण दिया गया।

कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर मोदी सरकार का जलाया पुतला

■ नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्दोष बताया गया है, इसको लेकर कोर्ट का फैसला सत्ता पर सत्य की जीत का प्रमाण है।

ईडी व अन्य संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग के विरोध में टोंक में कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार का पुतला जलाया ।

टोंक । जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा ईडी व अन्य संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग के विरोध में मुख्यालय स्थित घंटाघर चौराहा पर मोदी सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैरवा ने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्दोष बताया गया है, इसको लेकर कोर्ट का फैसला सत्ता पर सत्य की जीत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर मनगढ़ंत और झूठा मामला बनाकर गांधी परिवार की छवि को बिगाड़ने के लिए यह सब किया गया था। इस अवसर पर सरपंच संघ उपाध्यक्ष हंसराज फागणा, हामिद खान इत्यादि के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।- **आर अश्विन**

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरन ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी

लियोनेल मेस्सी

अर्जेंटीना- के फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अपने इंडिया टूर के समापन के बाद भारत के प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इस टूर में खूब मस्ती हुई और कुछ यादगार क्रॉसओवर पूरे देश में ट्रेंड कर रहे थे। अपने इंस्टाग्राम पर मेस्सी ने लिखा, ''नमस्ते भारत! दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं अविश्वसनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौरे के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है!''

क्या आप जानते हैं ?... विराट कोहली की 2025 में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने 651 रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6-0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच खेले गए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-0 से मैच जीता! मैच के 8वे एवं 78 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के 89 वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को 3-0 से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1-0 की बढ़त दे दी। इसके बाद राजस्थान ने विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापक्ति को छकाते हुए शानदार गोल कर के बढ़ते को 2-0 से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढ़त बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के 62 वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइकिल किक से गोल करे के बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद 72 वे मिनट मे नीरज ने और 81 वे मिनट मे मिलन और 82 वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को 6-0 से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ दा मैच चुना गया।

एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन-1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 240 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं! राज ने 46 और राकेश जांगिड ने 39 रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3 , मितेश जांगिड और नयन माली ने दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली! पुखराज कुमार ने 104 और पंकज जांगिड ने 61 रनों का योगदान दिया! केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेंद्र यादव और राहुल सैनी ने दो-दो विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.5 ओवर में 300 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाएं। आदित्य झाला ने 65, हार्दिक ने 64 और अभिषेक यादव ने 55 रनों का योगदान दिया। कैंडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी कैंडलविक क्रिकेट अकादमी 32 ओवर में 181 रन पर ऑल आउट हो गई! मेहुल सिंह ने सर्वाधिक 59 रनों का योगदान दिया। संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल किये

जयपुर, 17 दिसम्बर। पीपीसी पोलो ठाउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को 4.5 के मुकाबले 9 गोल से हराया। आधे गोल का एडवांटेज लेकर खेल रही बेदला पोलो टीम की ओर से सिद्धांत शर्मा ओर फ्रेडरिक ने 2-2 गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से हुर्रे अली ने 1 गोल ओर लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नया पावर हाउस, बसनी, जोधपुर, वेबसाइट:www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 64 के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है।

याचिका की प्रतियां आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/पठन के लिए उपलब्ध हैं और 200 रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती हैं:

1. लाइसेंसधारी का मुख्यालय – न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।
2. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बाड़मेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/बीकानेर/चूरू/जालौर/बालोतरा/फलोदी।

यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl/** और आरईसी की वेबसाइट पर भी। **www.rerc.rajasthan.gov.in**

जेडीवीवीएनएल द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सुबह 11:00 बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के सम्मेलन कक्ष में याचिका की ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं।

टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम 2021 के प्रपत्र-3 में एक शपथ-पत्र के साथ छह प्रतियों में प्राप्तकर्ता अधिकारी, आरईआरसी, विनियमक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास जमा कर सकते हैं, ताकि यह 06.01.2026 तक प्राप्तकर्ता अधिकारी तक पहुंच जाए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दायर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या 2380/25):

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	जेडीवीवीएनएल	
		अनुमत	ट्रू अप के लिए दावा किया गया
1	आय		
2	बिजली की बिक्री	20662	20768
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए एफएसए की वसूली	1437	
4	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	0	160
5	गैर-टैरिफ आय/अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू-अप क्रेडिट सहित)	406	1188
6	व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय	1	2
7	कुल राजस्व (ए)	22506	22118
8	व्यय		
9	प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत	16974	19995
10	संचालन एवं रखरखाव व्यय	1636	1361
11	टर्मिनल लाभ	370	1250
12	मूल्यह्रास	706	1091
13	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित)	666	1435
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	249	2584
15	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1981	
16	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	0	34
17	बीमा व्यय	26	0.50
18	अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मदों सहित)	0	(351)
19	कुल व्यय (ARR) (B)	22609	27399
20	अधिशेष/(अंतर) (C=A-B)	(103)	(5281)
21	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22	धारा 65 (डी) के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी	26	55
23	एफआरबीएम योजना (ई) के तहत हानि अनुदान	77	2485
24	अनुदान के बाद राजस्व अधिशेष/(अंतर) (F=C+D+E)	0	(2741)
25	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)	0	237
26	असाधारण आय/(व्यय) (एच)	0	2789
27	शुद्ध राजस्व अधिशेष / (अंतर) (F-G+H)	0	(188)

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
1	बिजली खरीद व्यय	18123
2	संचालन एवं रखरखाव व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1373
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	169
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	549
2.4	टर्मिनल लाभ	1326
3	मूल्यह्रास	1796
4	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित)	1664
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	264
6	विनियामक परिसंपत्तियों पर ब्याज	1565
7	प्रसारण शुल्क	2293
8	एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी शुल्क	12
9	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	-
10	कुल राजस्व व्यय	29133
11	लाभांश	-
12	आरओई पर कर	-
13	कुल राजस्व आवश्यकता	29133
14	घटाएं: गैर-टैरिफ आय	302
15	घटाएं: व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त आय	3
16	घटाएं: क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के मद में प्राप्त राशि	0
17	घटाएँ:व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त रसीद	0
18	खुदरा शुल्क से कुल शुद्ध राजस्व की आवश्यकता (13-14-15-16-17)	28828
19	मौजूदा टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व	23856
20	व्यापार से प्राप्त राजस्व	790
21	विनियामक अधिभार से राजस्व	2837
22	एफपीपीएएस से राजस्व	474
23	पीओसी से प्राप्त राजस्व	20
24	उपयुक्त सरकार से प्राप्त सब्सिडी (हानि सब्सिडी सहित)	2259
25	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष/(अंतर) (19+20+21+22+23+24-18)	1407
26	टैरिफ युक्तिकरण के बाद बिजली की बिक्री से राजस्व	23854
28	शुल्क युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(2)
29	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष (25+28) के लिए अधिशेष/(अंतर)	1405

तालिका 3: राज्य सीमा अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
राज्य सीमा के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)	40,532

तालिका 4 वितरण हानियाँ

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
वितरण हानि (%)	13.00%

डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रस्तावित की है:
तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना और वित्तपोषण के स्रोत (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मात्रा
1	प्रसारण एवं वितरण कार्यक्रम	1045
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	2044
3	आरडीएसएस (बुनियादी ढांचा)	807
4	आरडीएस (आरएमएस और आईटी/ओटी)	61
5	आरडीएसएस (छूटे हुए आरएचएच का विद्युतीकरण)	142
6	आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण)	775
7	कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए दो ब्लॉक आपूर्ति (आरडीएसएस)	290
8	आरडीएसएस (डीए-JUGA और छूटे हुए घरेलु कनेक्शन)	250
	कुल	5414
क्रमांक	**वित्तपोषण का स्रोत**	
1	ऋण	2588
2	अनुदान	1395
3	हिस्सेदारी	1113
4	उपभोक्ता योगदान	318
	कुल	5414

टिप्पणी:- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत व्यय 272 करोड़ रुपये है। हालांकि, पूंजी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटेक्स) मोड पर लागू किया जाना है।

डिस्कॉम ने क्रॉस सब्सिडी शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं:

तालिका 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार

वर्ग	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रु./किलोवाट घंटा)
व्हृद औधोयोगिक	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
मिश्रित भार- एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
अघरेलू-एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75

तालिका 7: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
132 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.01
33 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.11
11 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.63
कम वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	2.49

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

तालिका 9: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क

विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)
ग्रीन टैरिफ (रु./किलोवाट घंटा)	0.00*

* **टिप्पणी:**- डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-3) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:-मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में 650 पैसे (6.50 रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद 6.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर 650 पैसे प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करना और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रुझानों के अनुरूप होना है।
2. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना:डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटें मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और ऑफ-पीक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, ये उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक-घंटे के सरचार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुप्रयोग अनुचित हो जाता है।
3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआतविद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उपरोक्त दिशानिर्देशों के खंड 9 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अनिवार्य किया गया है, जो 31.03.2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7 गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान 1.3 गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वितरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निश्चित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।
4. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव:-डिस्कॉम्स ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में वर्तमान में कहा गया है कि जैसा कि नीचे दिया गया है:

   "यदि एमडीआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 11 केवी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।"

   डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें "दो बार से अधिक" वाक्यांश को "तीन बार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें "दो बार से अधिक" का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। TCOS-2021 के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से 5% से अधिक मांग होने पर टैरिफ में बदलाव लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकरूपता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।
5. 5 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी में स्लैबों का विलय।:याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा गैर-घरेलू (एनडीएस) टैरिफ संरचना जटिल है और इससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता बढ़ाने और टैरिफ के आवेदन को सरल बनाने के लिए, डिस्कॉम ने 200 यूनिट तक के गैर-घरेलू खपत स्लैब को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, 5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले एनडीएस उपभोक्ताओं के लिए, डिस्कॉम ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संशोधित एकीकृत टैरिफ संरचना का प्रस्ताव दिया है।

गैर-घरेलू सेवा	मांग/निश्चित शुल्क (रु.)	ऊर्जा शुल्क (रु./यूनिट)
5 किलोवाट तक के एससीएल के लिए एनडीएस		
एनडीएस प्रकार 1		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	350	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
एनडीएस प्रकार 2		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	450	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		
एनडीएस प्रकार 3		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	700	7.00
प्रति माह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक की खपत।		
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक की खपत		8.50
प्रति माह 500 यूनिट से अधिक की खपत		

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट श्रेणी के लिए निश्चित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करना: डिस्कॉम्स ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निश्चित शुल्क बहुत अधिक हैं। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई लैंप पॉइंट जुड़े होते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम्स पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निश्चित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट	मांग/निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनिट)
जनसंख्या <1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 150 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 3000 रुपये के अधीन।	7.00
जनसंख्या >1 लाख	प्रति लैंप पॉइंट 200 रुपये प्रति माह, प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह अधिकतम 8000 रुपये के अधीन।	7.50

टिप्पणी:- याचिका में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियंता (RA&C)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राज.संवाद/सी/25/15997

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर, वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 64(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62 और 64 सपठित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2019 समयानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनिश्चियन की निबन्धन व शर्तें) विनियम 2025 तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम 2006 के अन्तर्गत विव. 2024–25 की समग्र राजस्व आवष्यकता की ट्रूईंग–अप, विव. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है।

याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 200/– के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :–

1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय– विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर।
2. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), अविविनिलिः– ब्लॉक–आई, हाथीभाटा पॉवर हाऊस, अजमेर–305001।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर/ब्यावर/भीलवाडा/उदयपुर/सलुम्बर/झुंझुनू/नागौर/सीकर/चितौडगढ/बांसवाड़ा/राजसमन्द/डूंगरपुर/प्रतापगढ/डीडवाना–कुचामन स्थित कार्यालय।

याचिका **www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl** (अजमेर डिस्काम की वेबसाइट) और आरईआरसी की वेबसाईट **www.rerc.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव्य–दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक 26.12.2025 (शुक्रवार) को सभागार, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर 12 बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते है।

टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति सहायक प्रपत्रों और राविविआ (कार्य सम्पादन) विनियम 2021 के फार्म सं0 3 में शपथपत्र सहित प्राप्ति अधिकारी, राविविआ, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर – 302001 के पते पर 6 प्रतियों में भेज सकते हैं जिससे कि ये प्राप्ति अधिकारी के पास दिनांक 09.01.2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जायें।

विव. 2024–25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग–अप, विव. 2026–27 के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2379/2025):–

सारिणी 1 : विव. 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रू अप का सारांश (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विवरण	अजमेर डिस्कॉम	
		स्वीकृत	ट्रू अप के लिये किया गया दावा
1.	राजस्व		
2.	ऊर्जा विक्रय	21,496	20,926
3.	वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिये फ्यूल सरचार्ज की वसूली	1370	
4.	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	0	128
5.	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय (आरवीपीएन/आरवीयूएन के ट्रू–अप क्रेडिट सहित)	497	843
6.	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	4	3
7.	कुल राजस्व (अ)	23,367	21,899
8.	व्यय		
9.	ऊर्जा क्रय लागत प्रसारण शुल्क सहित	15,616	15,451
10.	पवस व्यय	1582	1519
11.	सेवान्त लाभ	570	771
12.	ह्रास	701	1119
13.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	798	895
14.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	158	2024
15.	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	1489	
16.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	0	(2)
17.	बीमा व्यय	30	1
18.	अन्य व्यय (उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट सहित)	315	228
19.	**कुल व्यय स.रा.आ. (ब)**	**21259**	**22006**
20.	**अधिशेष /(कमी) (स= अ–ब)**	**2108**	**(107)**
21.	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22.	धारा 65 के तहत सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	18	0
23.	एफआरबीएम योजना के तहत् सब्सिडी (ई)	0	0
24.	सब्सिडी के बाद राजस्व अधिशेष/(कमी) (एफ=स+द+ई)	2126	(107)
25.	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)		134
26.	असाधारण आय/ (व्यय) (एच)		1982
27.	**कुल राजस्व अधिशेष/(अन्तर) ट्रूअप (एफ–जी+एच)**	**2126**	**1742**

सारिणी 2 : विव. 2026-27 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू. में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026–27
1.	विद्युत क्रय व्यय	14464
2.	पवस व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1168
2.2	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	200
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	530
2.4	सेवान्त लाभ	818
3	ह्रास	1663
4.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	1042
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	198
6.	नियामक सम्पत्ति पर ब्याज	813
7.	प्रसारण अधिभार	1830
8.	एन.एल.डी.सी./आर.एल.डी.सी./एस.एल.डी.सी. अधिभार	9
9.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	–
10.	**कुल राजस्व आय**	**22736**
11.	साम्या पर प्रतिफल	–
12.	साम्या पर कर	–
13.	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**22736**
14.	घटायें – गैर टैरिफ आय	546
15.	घटायें– व्हीलिंग प्रभार से आय	3
16.	घटायें–क्रास सब्सिडी से प्राप्तियां	0
17.	घटायें– व्हीलिंग पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां	0
18.	**खुदरा दरों से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (13–14–15–16–17)**	**22188**
19.	वर्तमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से आय	22198
20.	ट्रेडिंग गतिविधि से आय	194
21.	नियामक अधिभार से राजस्व	2461
22.	एफपीपीएएस से राजस्व	415
23.	पीओसी से राजस्व	45
24.	सरकार से सब्सिडी (हानि सहायिकी सहित)	0
25.	**मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिये राजस्व अधिशेष/कमी (19+20+21+22+23+24-18)**	**3125**
26.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व	22194
27.	युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(4)
28.	**टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष हेतु अधिशेष/(घाटा) (25+27)**	**3121**

सारिणी 3 : राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026–27
राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)	33,419

सारिणी 4: वितरण हानि (%)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2026–27
वितरण हानियां (%)	7.50%

डिस्कॉम ने विव. 2026-27 के लिये निवेश योजना निम्नानुसार प्रस्तावित की है:-
सारणी 5 - वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये निवेश योजना तथा निधियन के स्त्रोत (करोड रुपये)

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
1.	उप प्रसारण व वितरण	700
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	1520
3.	आरडीएसएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	700
4.	आरडीएसएस (आईटी/ओटी)	64
5.	आरडीएसएस (फीडर पृथक्करण)	2242
6.	आरडीएसएस (डीए–जेजीयूए)	21
	कुल	5248
क्र. सं.	**निधियन के स्त्रोत**	**राशि**
1.	ऋण	1414
2.	अनुदान	1828
3.	अंशपूंजी	1881
4.	उपभोक्ता योगदान	125
	कुल	5248

क्रॉस सब्सिडी अधिभार, व्हीलिंग प्रभार, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन पॉवर टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव भी डिस्कॉम ने निम्नानुसार दिया है:–

सारिणी 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार

श्रेणी	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रू. प्रति यूनिट)
वृहद श्रेणी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
मिश्रित भार – एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
अघरेलू – एचटी	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75

सारिणी 7 : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग प्रभार (रू. प्रति यूनिट)

132 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.01
33 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.11
11 केवी पर व्हीलिंग प्रभार	0.63
एलटी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग प्रभार	2.49

सारणी 8- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार (रू. प्रति यूनिट)

अतिरिक्त अधिभार	0.47

सारिणी 9 : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित ग्रीन पॉवर टैरिफ

विवरण	(रू. प्रति यूनिट)
ग्रीन पॉवर टैरिफ	0.00*

* **नोटः**– डिस्कॉम ने उन उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है जो डिस्कॉम से ग्रीन पावर लेना चाहते हैं। ग्रीन पावर उसी रेट पर दी जायेगी जो किसी सम्बन्धित श्रेणी के लिये लागू है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण उपायों की मांग की है:–

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एम.पी./एचटी–3) के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी:–

अनुसूची एम.पी./एचटी–3 मध्यम औद्योगिक सेवा के तहत् ऊर्जा शुल्क वर्तमान में रूपये 6.50 प्रति यूनिट निर्धारित हैं। सभी लागू छूटों को शामिल करने के बाद, एचटी–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क रूपये 6.30 प्रति यूनिट निर्धारित होता है। डिस्कॉम प्रस्तावित करता है कि एचटी–3 उपभोक्ताओं के लिये सभी छूटों के बाद न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को 6.00 रूपये प्रतियूनिट तक संशोधित किया जाए, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर को 6.50 रूपये प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रखा जाए। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस संशोधन का लक्ष्य राज्य में सामर्थ्य बढ़ाने और औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने हेतु निर्धारित किया है। यह संशोधन प्रचलित बाजार स्थितियों और आपूर्ति प्रवृत्तियों की लागत तथा याची की वित्तीय व्यवहार्यता की सुनिश्चितता को ध्यान में रख किया है।

2. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये टॉइम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ हटाना:–

डिस्कॉम सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग उपभोक्ता श्रेणी के लिये टॉइम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ की प्रयोजकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग स्थापनाएँ मुख्य रूप से शाम और रात के शुरूआती घंटों में, आम तौर पर सूर्यास्त से लेकर मध्यरात्रि या सुबह जल्दी तक होती है और लोड को ऑफ–पीक समय में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जो टीओडी टैरिफ का मुख्य हिस्सा है। इसलिये, इन उपभोक्ताओं को न तो सोलर घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का फायदा मिलेगा और न ही वे पीक आवर सरचार्ज से बच पायेंगे, जिससे टीओडी एप्लीकेशन पीएसएल श्रेणी के लिये असमान हो जायेगी।

3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिये सिंगल–पार्ट टैरिफ की शुरुआतः–

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिये दिशा–निर्देश 2024 जारी किये है। इन दिशा–निर्देशों का बंध 9 की गाइडलाइंस में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिये सिंगल पार्ट टैरिफ जो कि 31.03.2028 तक सप्लाई की औसत आपूर्ति लागत यथा सोलर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान 0.7xऔसत आपूर्ति लागत और नॉन–सोलर घंटों के दौरान 1.3xऔसत आपूर्ति लागत पर कैप होगा, की अनिवार्यता की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेषनों को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लागू मौजूदा स्थायी शुल्कों को हटाकर एकल–भार टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव करता है।

4. विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–2025 की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्तावः

विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–2025 की परिभाषा 17 वर्तमान में यह वर्णित करता हैः–

अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक पाये जाने पर एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार मांग 50 केवीए से अधिक होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिए जाने के दो माह की अवधि के अन्दर–अन्दर 11 के.वी. पर आपूर्ति लेनी होगी, जिसमें विफल होने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति के टैरिफ के नियम 17 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ''दो से ज्यादा'' वाक्यांश को 'तीन' से बदला जाए। मौजूदा शब्दों में अस्पष्टता है इसमें 'दो से ज्यादा बार' का जिक्र है, जबकि तीसरे बार होने पर कार्रवाई की जरूरत है। टीसीओएस–2021 का बंध 4.8(b) निर्दिष्ट करता है कि अगर एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार अधिकतम डिमाण्ड 5 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है, तो चेंज ओवर लागू होगा। इसलिये डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 को टीसीओएस के साथ मिलाने से स्पष्टता, निरंतरता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी।

5. 5 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिये गैर–घरेलू श्रेणी में स्लैब का विलयः

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिये मौजूदा टैरिफ संरचना में कुछ जटिलताएँ है, जिससे परिचालन संबंधी चुनौतियाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता और सरल टैरिफ अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम 200 यूनिट तक की खपत के लिये गैर–घरेलू स्लैब को एक एकल स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव करता है। डिस्कॉम द्वारा 5 किलोवाट तक की स्वीकृत संबंद्ध भार वाले एनडीएस श्रेणी के लिये संशोधित टैरिफ संरचना प्रस्तावित है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित हैं:

अघरेलू सेवा	संविदा/स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)
अघरेलू 5 किवा तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार		
अघरेलू प्रकार–1		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	350	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
अघरेलू प्रकार–2		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	450	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग		
अघरेलू प्रकार–3		
प्रतिमाह पहले 100 यूनिट तक उपभोग	700	7.00
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक और 200 यूनिट तक उपभोग		8.50
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक और 500 यूनिट तक उपभोग		
प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक तक उपभोग		

6. सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा की पुनः शुरूआतः

डिस्कॉम प्रस्तुत करता है कि विव 2025–26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये मौजूदा स्थाई प्रभार बहुत ज्यादा हो गया हैं। यह स्थिति पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से नगर पालिकाओं और सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग व्यवस्था के लिये जिम्मेदार स्थानीय प्राधिकरणों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं के पास एक सेवा कनेक्शन से जुड़े कई लैंप पॉइंट होते हैं तथा ऐसे उपभोक्ताओं के लिये स्थाई प्रभार प्रति लैंप पॉइंट के आधार पर परिकल्पित किये जाते है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिये, डिस्कॉम्स सार्वजनिक स्ट्रीट लाईटिंग श्रेणी के लिये सेवा कनेक्शन स्थाई प्रभार पर अधिकतम सीमा को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखता हैं। इस उपाय का उद्देष्य डिस्कॉम के राजस्व की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना नगर निकायों के लिये वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को समर्थन मिल सकें।

पीएसएल श्रेणी के लिये प्रस्तावित टैरिफ संरचना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई हैं:

सार्वजनिक स्ट्रीट लाईट	संविदा/स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
जनसंख्या एक लाख से कम	3000/– रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 150 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह	7.00
जनसंख्या एक लाख या एक लाख से अधिक	8000/– रू. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यधीन 200 रूपये प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह	7.50

नोट :– 1. विस्तृत विवरण याचिका में उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
याचिकाकर्ता के निमित्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राज.संवाद/सी/25/15937

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आहोर में जालोर जिले के 338 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

जालोर/जयपुर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता सहित, विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

शर्मा बुधवार को आहोर (जालोर) में ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर में लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात की व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चैक वितरित किए।**

शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज जालोर में 338 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18 हजार किसानों के खेतों में 10 हजार 432 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।

आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जालोर और आहोर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को रेखांकित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविरों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित, विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक जीवाराम चौधरी सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आहोर में जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए।

एच वन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10,400 से ज्यादा कर्मचारियों की थीं, पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगती, जिसमें वीज़ा शुल्क के रूप में कुल रकम एक अरब डॉलर से भी अधिक हो गई होती।

टाटा को इस अवधि में 6,500 कर्मचारियों के लिए फीस देनी पड़ती, जो नए स्वीकृत एच-1बी कर्मचारियों का 82 प्रतिशत है। वहीं कॉग्निज़ेंट को 5,600 से अधिक कर्मचारियों, यानी 89 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों के लिए यह शुल्क चुकाना पड़ता। भले ही कानूनी चुनौतियों के जरिए इस शुल्क को जल्दी रोक दिया जाए, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीज़ा की मांग में भारी गिरावट आएगी और अधिक कर्मचारियों को विदेशों में ही तैनात किया जाएगा।

इमिग्रेशन वकील जोनाथन वासडेन, जो कई आईटी नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा, हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। डर यह है कि अगर विदेशों में वास्तव में असाधारण प्रतिभा हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अवसर से वंचित रह जाएंगे।

'अरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थरूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी डाला। मनीष तिवारी भी इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका एसआईआर पर पहला भाषण आंखें खोलने वाला और सराहनीय प्रयास था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के रूप में देखा गया।

अब तक राहुल गांधी का रुख यही था कि "अगर पार्टी छोड़नी है, तो आप यह करने के लिए स्वतंत्र हैं", लेकिन लगता है कि हाल के समय में उनका रुख बदल गया है।

'दिल्ली में अब बीएस-4 या उससे अधिक स्टैंडर्ड के वाहन ही चलेंगे'

दिल्ली में प्रदूषण में कटौती करने के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

नयी दिल्ली,17 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी, जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।

न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं, बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।

- **इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पुराने डीज़ल वाहनों व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।**

न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच संवाद का उद्देश्य आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों को सशक्त करना बताया गया।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी व सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर।

इसे गांधी परिवार के लिए एक तरह से "राहत" माना गया, लेकिन भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीया ने इसे "भ्रामक हैडलाइन और दावा" करार दिया, क्योंकि इसमें "कोई राहत नहीं थी।"

मालवीया के अनुसार, अदालत ने "कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यु) ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी नए सिरे से केस को आगे बढ़ा सकता है। एफआईआर के कारण ईडी की दलीलें पीएमएलए के तहत वैध और प्रक्रियागत रूप से मान्य हो जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "असल में, अदालत ने ईडी की चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें प्रक्रिया संबंधी गलतियां थीं, जिनमें पीएमएलए के तहत निर्धारित एफआईआर का नहीं होना भी शामिल था। भाजपा नेता यह तर्क कर रहे हैं। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि गांधी परिवार और उनके सहयोगियों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके एजेएल (नेशनल हैरल्ड का प्रकाशक) पर नियंत्रण प्राप्त किया था, और इसमें 90 करोड़ रुपये के ऋणों का हेरफेर भी शामिल था।

- **जैसा कि विदित ही है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ईडी ने केवल एक व्यक्ति, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग की जाँच शुरु कर दी थी, यह गैर कानूनी है, क्योंकि पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही मनी लॉण्डरिंग कानून के तहत जाँच हो सकती है।**

'भारत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

यह पांच दिवसीय दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषित किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी व्यापक आलोचना की थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की बार-बार की विदेश यात्राएं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाती हैं।

'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रैली में यह बात कही, "सेवन सिस्टर्स भारत से अलग कर दी जाएगी।" यह रैली उन लोगों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी के हमले में शामिल थे, और यह दावा किया जा रहा था कि आरोपियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। अब्दुल्ला द्वारा की गई यह उत्तेजक टिप्पणी उस समय आई, जब बाँग्लादेश इस सप्ताह के शुरु में अपना 55वां विजय दिवस मना रहा था। इस बीच, भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है तथा विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, "हम उम्मीद करते हैं कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी, जिससे शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

'सबका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा एक प्रतिशत थी। सभी बीमा कंपनियों और बिचौलियों के लिए अपने नाम में "बीमा" शब्द रखना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908